20th Year
Issue: 129
12.09.2026 (SATURDAY)
ROURKELA
R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
(Pages-6)
Price:2.00

दैनिक कलिंग समाचार
The kalingasamachar
e-paper-www.thekalingasamachar.com
प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल
Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

मोदी-पुतिन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर हुई वार्ता

नयी दिल्ली ११/०९ (संवाददाता): भारत की राजधानी दिल्ली में सुहावने मौसम के बीच जब दो मित्र देश भारत और रूस के राष्ट्राध्यक्ष मिले तो द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, व्यापार बढ़ाने, रक्षा सौदों आदि को लेकर तो व्यापक वार्ता हुई ही साथ ही यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष बड़ी प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा, दोस्त भारत के लिए रूस ने जिस तरह एक से एक घातक रक्षा उपकरण और तकनीक देने के प्रस्ताव सामने रख दिये हैं उससे पूरी दुनिया में खलबली मच गयी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भी साथ होते हैं, तो उनकी बातचीत ही नहीं, उनके हावभाव भी दुनिया को कई बड़े संदेश देते हैं, इस बार भी ऐसा ही हुआ। क्क्क्कष्ट्स शिखर सज़्मेलन से पहले मोदी और पुतिन की करीब 45 मिनट चली द्विपक्षीय बातचीत और उसके बाद दोनों नेताओं का एक ही कार में भारत मंडपम पहुंचना उस भरोसे का संकेत है जिसने दशकों पुराने भारत-रूस संबंधों को बदलती विश्व व्यवस्था में भी मजबूती से टिकाए रखा है।

हम आपको बता दें कि इस वर्ष दोनों नेताओं की यह दूसरी बैठक है। बैठक में भारत-रूस द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल गतिशीलता और जन-जन संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल रहे। दोनों नेताओं ने 9 से 11 सितंबर तक पहली बार भारत में आयोजित रूस की अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी 'ढ्ढहृहृक्काहृरू ढ्ढठ्ठस्त्रढ्ढ' का भी दौरा किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। इसके अलावा ब्रिज़्स में भारत की 2026 की अध्यक्षता, पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र के संघर्षों सहित विभिन्न क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता दोहराते हुए शांति प्रयासों में भारत की भूमिका की पेशकश की।

दोनों नेताओं ने भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सज़्मेलन के लिए रूस आने का

निमंत्रण दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया। सज़्मेलन की तारीख आपसी सहमति से राजनयिक माध्यमों के जरिए तय की जाएगी।

साथ ही दिलचस्प और बेहद महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रक्षा और रणनीतिक सहयोग के इतने बड़े एजेंडे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की बातचीत में भी यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाया और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने युद्ध खत्म करने तथा शांति की दिशा में आगे बढ़ने की भारत की स्पष्ट सोच रखी। हम आपको यह भी याद दिला दें कि करीब 11 दिन पहले यानि 31 अगस्त को भी किर्गिस्तान के बिश्केक में स्ह्ल शिखर सज़्मेलन के दौरान मोदी ने पुतिन से सीधे कहा था कि अब दुनिया को अनंत युद्ध से निकलकर युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ना चाहिए और हर दिन जारी रहने वाला युद्ध मानवता को पीछे धकेलता है। यहां मोदी की कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण दिखाई देता है। जिस समय पश्चिमी देश रूस पर दबाव, प्रतिबंध और अलगाव की नीति अपना रहे हैं, उसी समय भारत रूस के साथ अपनी रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक साझेदारी को मजबूती से जारी रखते हुए उसके सर्वोच्च नेतृत्व के सामने युद्ध समाप्त करने की बात कहने की स्थिति में है। यह ताकत किसी दबाव की राजनीति से नहीं, बल्कि भरोसे की उस असाधारण पूंजी से पैदा हुई है जिसमें भारत रूस का मित्र और रणनीतिक साझेदार है, लेकिन रूस की हर नीति का आंख मूंदकर समर्थक नहीं है। मोदी पुतिन से असहमति व्यक्त कर सकते हैं, युद्ध खत्म करने की अपील कर सकते हैं और साथ ही भारत-रूस रक्षा साझेदारी को भी आगे बढ़ा सकते हैं, यही भारत की स्वतंत्र और बहुध्रुवीय विदेश नीति की असली ताकत है।

उधर, मोदी और पुतिन की आज की मुलाकात से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि मॉस्को भारत के सामने केवल हथियार बेचने का प्रस्ताव नहीं रख रहा, बल्कि रक्षा तकनीक, संयुक्त उत्पादन और संभावित संयुक्त विकास का ऐसा पैकेज रख रहा है, जिसका सीधा असर एशिया से लेकर वैश्विक सामरिक समीकरणों तक दिखाई दे सकता है।

रूस ने भारत में Su-57 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के संयुक्त उत्पादन, इंजन तकनीक साझा करने, अतिरिक्त S-400 प्रणालियों, Pantsir-SvM, आधुनिक रडार और रणनीतिक पनडुज़्बियों से जुड़े प्रस्ताव सामने रखे हैं।

हम आपको बता दें कि सबसे बड़ा दांव Su-57 पर है। रूस भारत को दो स्क्वाड्रन विमान सीधे देने के साथ भारत में तीन से पांच अतिरिक्त स्क्वाड्रनों के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दे रहा है। इससे भी आगे बढ़कर मॉस्को स्ह्व-57 के इंजन से जुड़ी तकनीक भारत के साथ साझा करने को तैयार है, ताकि उसके महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण भारत में हो सके।

हालांकि यह तकनीकी सहयोग Su-57 की खरीद से जुड़ा हुआ है। यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है ज़्योंकि भारत अपनी स्वदेशी ,स्ह्र परियोजना के आने तक पांचवीं पीढ़ी की लड़ाकू क्षमता में संभावित अंतर को भरने के विकल्प तलाश रहा है।

ब्रिक्स बिजनेस फोरम में बोले पीएम मोदी, भारत नेविगेशन की आजादी का करता है समर्थन

नयी दिल्ली ११/०९ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ग्लोबल इकॉनमी में भारत की बढ़ती भूमिका पर ज़ोर देते हुए कहा कि जब दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता का सामना कर रही है, तब भी भारत विकास कर रहा है। ब्रिज़्स बिज़नेस फ़ोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब दुनिया अस्थिरता के दौर से गुज़र रही है, तब भारत विकास कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच, आज भारत विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का स्रोत बना हुआ है।

बदलती ग्लोबल इकॉनमी में ब्रिज़्स की भूमिका पर पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिज़्स ग्लोबल इनोवेशन और समाधानों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। उन्होंने इस समूह से और ज़्यादा सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा, आइए ब्रिज़्स की महत्वाकांक्षा को कार्रवाई में और सामूहिक ताकत को ग्लोबल समाधानों में बदलें। ब्रिज़्स आगे बढ़े और दुनिया को भी आगे ले जाए। ग्लोबल ट्रेड के प्रति भारत के नज़रिए पर ज़ोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज, जब दुनिया भर में व्यापार की बाधाएं बढ़ रही हैं, भारत आर्थिक पुल बना रहा है।

उन्होंने मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड के संदेश के साथ ग्लोबल मैन्युफैक्क्रिंग और इनोवेशन के लिए भारत के विज़न को भी सामने रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इकॉनमी के लिए सुरक्षित समुद्री रास्तों के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा कि ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब समुद्री रास्ते सुरक्षित हों, सप्लाई रूट खुले हों और नाविक सुरक्षित हों। इसीलिए भारत नेविगेशन की आज़ादी और नाविकों की सुरक्षा का मज़बूती से समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस साल ब्रिज़्स के 20 साल पूरे हो रहे हैं और ब्रिज़्स परिवार में 21 देश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह समूह दुनिया की 50त्न आबादी, 40 प्रतिशत ग्लोबल ह्लष्ठक्क और 20 प्रतिशत ग्लोबल ट्रेड का प्रतिनिधित्व करता है।

एकतरफावाद के खिलाफ ब्रिक्स बनेगा मजबूत आवाज-हिमंत विस्वासरमा

नयी दिल्ली ११/०९ (संवाददाता): असम के मुज़्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 11 सितंबर को कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट के दौरान, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति को देखते हुए, दुनिया का नेतृत्व करने की ब्रिज़्स की ऐतिहासिक ज़िज़्मेदारी है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह समूह शांति और समृद्धि की दिशा में काम करेगा। सरमा ने भारत द्वारा ब्रिज़्स शिखर सज़्मेलन की मेज़बानी को एक बड़ी उपलज़्धि बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अध्यक्षता का स्वागत किया। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि भारत में ब्रिज़्स शिखर सज़्मेलन का आयोजन एक अनोखी उपलज़्धि है। पूरी दुनिया में, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य और अन्य जगहों पर चल रहे संकट के बीच, दुनिया का नेतृत्व करने की ब्रिज़्स पर एक बड़ी ऐतिहासिक ज़िज़्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिज़्स का अध्यक्ष है। निश्चित रूप से, ब्रिज़्स दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए एक ठोस कार्य

योजना लेकर आएगा। ये बातें ऐसे समय में कही गई हैं जब भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें ब्रिज़्स शिखर सज़्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। भारत की 2026 की अध्यक्षता लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण थीम के तहत काम करती है, जिसमें विकास, स्थिरता और नवाचार मुज़्य फोकस क्षेत्र हैं। इस बीच, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन शिखर सज़्मेलन में भाग लेने के लिए 11 सितंबर को नई दिल्ली पहुंचे और दिन में बाद में प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। तेहरान से रवाना होने से पहले, पेज़ेशकियन ने कहा कि एकतरफावाद का मुकाबला करने में ब्रिज़्स की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्होंने आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए नए तरीकों की वकालत की।

पीएम मोदी की नेतृत्व में ब्रिक्स में भारत की धमक, भारत अहम सदस्य बनकर उभरा-सुधांशु त्रिवेदी

नयी दिल्ली ११/०९ (संवाददाता): भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत ब्रिज़्स का एक अहम सदस्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में इस समूह में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिज़्स शिखर सज़्मेलन के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, त्रिवेदी ने बदलती वैश्विक परिस्थितियों और दुनिया भर में जारी संघर्षों के बीच इस सज़्मेलन के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिज़्स शिखर सज़्मेलन शुरू हो गया है और बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह समूह दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40त्न हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष चल रहे हैं, यह मंच और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने भारत द्वारा समिट की मेज़बानी करने को गर्व की बात बताया और संगठन में देश की बदलती

भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत इस समिट की मेज़बानी कर रहा है। पिछले 12 सालों में ब्रिज़्समें भारत की स्थिति में आया बदलाव उल्लेखनीय है। त्रिवेदी ने दावा किया कि 2014 से पहले, भारत को ब्रिज़्स के एक कमज़ोर और कम अहमियत वाले सदस्य के तौर पर देखा जाता था, और कुछ लोग तो संगठन में भारत की लगातार भागीदारी पर भी सवाल उठाते थे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले, भारत को ब्रिज़्स के एक कमज़ोर और कम अहमियत वाले सदस्य के तौर पर देखा जाता था, और कुछ लोग तो यह भी सवाल उठाते थे कि ज़्या भारत को इस समूह में बने रहना चाहिए।उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अब भारत ने खुद को एक अहम सदस्य के तौर पर स्थापित कर लिया है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दूसरे ब्रिज़्स देशों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। त्रिवेदी ने कहा कि आज भारत ब्रिज़्स के एक अहम सदस्य के तौर पर उभरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिज़्स लीडर्स समिट की मेज़बानी कर रहा है। उज़्मीद है कि इस विस्तारित समूह में व्यापार और विज़ीय सहयोग, टेज़्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा सुरक्षा, ज़्लाइमेट एज़्शन और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी।

पश्चिम बंगाल में 15000 करोड़ रुपये का प्रोजेज़्ट शुरू-सुवेंदु अधिकारी

कोलकाता ११/०९ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल के मुज़्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 11 सितंबर को राज्य में विकास की कई अहम योजनाओं के बारे में बताया। इनमें 15,000 करोड़ रुपये का एक प्रोजेज़्ट, 600 करोड़ रुपये की अमूल सुविधा और रोबोटिक फायर-फाइटिंग सिस्टम शामिल हैं। यह सिस्टम ऐसी जगहों तक पहुँचने के लिए बनाया गया है जहाँ आम फायर टेंडर नहीं पहुँच पाते। पिछले चार महीनों में हुई प्रगति का ज़िक्र करते हुए अधिकारी ने कहा कि पिछले चार महीनों में हमने कई अहम प्रोजेज़्ट देखे हैं; जैसे, गंगोनी में एक प्रोजेज़्ट के लिए 700 करोड़ रुपये का बड़ा वादा किया गया था। 15,000 करोड़ रुपये का एक बहुत बड़ा प्रोजेज़्ट भी शुरू हो चुका है। रोबोटिक फायर-फ़ाइटिंग सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा कि हम रोबोटिक फ़ायर-फ़ाइटिंग सिस्टम जैसे

प्रोजेज़्ट्स में तरक्की देख रहे हैं, जो ऐसी जगहों पर काम कर सकते हैं जहाँ बड़ी फ़ायर ट्रक नहीं पहुँच सकतीं। अधिकारी ने अमूल के 600 करोड़ रुपये के प्रोजेज़्ट पर काम शुरू होने का भी ज़िक्र किया और कहा, तीसरा बड़ा प्रोजेज़्ट अमूल से जुड़ा है, जिसमें 600 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। काम पहले ही शुरू हो चुका है और एक बड़ी फ़ैसिलिटी बनाई जा रही है।

उन्होंने लार्सन एंड टुब्रो के एक बड़े डेटा सेंटर के उद्घाटन का भी ज़िक्र किया और कहा कि हमने रुञ्ज के एक बड़े डेटा सेंटर का उद्घाटन किया; कैबिनेट ने इस प्रोजेज़्ट को पहले ही मंज़ूरी दे दी है। मुज़्यमंत्री ने ये बातें कोलकाता में सॉल्ट लेक सिटी सेंटर के पास स्टाइल बाज़ार में आयोजित फ़ैशन वॉर्डरोब इवेंट में कहीं, जहाँ विज़ मंत्री स्वपन दासगुप्ता भी मौजूद थे। उनके ये बयान पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव से पहले आए हैं, जो 6 अज़्टूबर को होने हैं (इसमें नंदीग्राम सीट भी शामिल है) और वोटों की गिनती 9 अज़्टूबर को होगी। नंदीग्राम सीट तब खाली हुई थी जब अधिकारी ने, जिन्होंने विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटें जीती थीं, भवानीपुर सीट अपने पास रखने का फैसला किया। शुभंकर सरकार ने नंदीग्राम में कथित तौर पर विकास न होने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि मुज़्यमंत्री को यह सीट अपने पास रखनी चाहिए थी।

तलाक-ए-हसन तलाक का वैध तरीका, देश में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं-गुवाहाटी उच्च न्यायालय

गुवाहाटी ११/०९ (संवाददाता): गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने तलाक के पंजीकरण से जुड़ी एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि 'तलाक-ए-हसन' मुस्लिम समुदाय में तलाक का एक वैध जरिया है और मौजूदा समय में देश में इस प्रक्रिया पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह ऐतिहासिक आदेश न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका का निपटारा करते हुए पारित किया।

अदालत ने एक याचिकाकर्ता को अपने तलाक का पंजीकरण कराने के लिए असम मुस्लिम विवाह एवं

तलाक अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम, 2024 के तहत बारपेटा क्षेत्र के विवाह एवं तलाक पंजीयक से संपर्क करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी ने 'तलाक-ए-हसन' के जरिए दिए गए तलाक के पंजीकरण से संबंधित एक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसकी शादी 2016 में हुई थी। बाद में दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए और उसकी पत्नी ने कथित तौर पर 2018 में अपना ससुराल छोड़ दिया। दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिशें भी सफल नहीं हुईं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 22 मार्च, 26 अप्रैल और 27 मई 2026 को तीन अलग-अलग तारीखों पर 'तलाक-ए-हसन' दिया और फिर कानून के तहत तलाक के पंजीकरण के लिए संबंधित प्राधिकारी से संपर्क किया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि 'तलाक-ए-हसन' पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उसने इसकी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तलाक दिया है। राज्य सरकार ने हालांकि अदालत से कहा कि 1935 के पुराने कानून को निरस्त किया जा चुका है और उसके तहत नियुक्त प्राधिकारी का पद भी समाप्त कर दिया गया है इसलिए उस व्यवस्था के तहत अब तलाक का पंजीकरण नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया 'तलाक-ए-हसन', तलाक का वैध तरीका है और मौजूदा समय में देश में इस पर प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, अदालत ने 1935 के कानून के तहत बारपेटा में नियुक्त प्राधिकारी को तलाकनामा पंजीकृत करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया ज़्योंकि वह कानून निरस्त किया जा चुका है और उसके तहत सृजित पद भी समाप्त कर दिया गया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को 2024 के कानून के तहत संबंधित क्षेत्र के विवाह एवं तलाक पंजीयक से संपर्क करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि पंजीयक को यह जांच करनी होगी कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में तलाक दिया है या नहीं और उसे उसकी पहचान की पुष्टि करनी होगी। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी को उचित मंच पर 'तलाक-ए-हसन' को चुनौती देने की स्वतंत्रता होगी। याचिकाकर्ता की पत्नी नोटिस दिए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने इन निर्देशों के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया।

विविध समाचार

नीम करौली बाबा पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने 10 लाख से शुरू होकर कमाए 200 करोड़

मुंबई ११/०९ (संवाददाता):नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' सात अगस्त को जब सिनेमाघरों में आई तो न उसके साथ किसी बड़े सितारे का नाम जुड़ा था और न ही उसे लेकर कोई चर्चा थी। यहां तक की टिकट खिड़की पर कोई खास हलचल नहीं हुई, लेकिन कुछ ही हज़्तों में तस्वीर ऐसी बदली कि 10 लाख रुपये से शुरुआत करने वाली यह फिल्म 200 करोड़ रुपये की कमाई तक पहुंच गई। टिकट खिड़की पर फिल्म के धमाकेदार प्रदर्शन ने 51 साल पहले आई फिल्म 'जय संतोषी मां' को मिली अप्रत्याशित सफलता की याद दिला दी।

डॉज़्टर से फिल्मकार बने विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी 'हनुमान अंश' में अभिनेता शोभिनव सत्या मुज़्य भूमिका में हैं जिन्हें इस फिल्म के रिलीज होने से पहले अभिनय जगत में शायद ही कोई जानता था। सात अगस्त को महज 250 स्क्रीन पर रिलीज हुई यह फिल्म अब 2,000 स्क्रीन तक पहुंच चुकी है। यह फिल्म उज़राखंड के संत बाबा नीब करौरी के जीवन को परदे पर उतारती है। फिल्मउपकरण खोजें

उनके भक्तों में हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी एवं अभिनेत्री अनुष्का शर्मा जैसे चर्चित नाम शामिल हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि स्टीव जॉज़्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे कारोबारी दिग्गज भी उज़राखंड के कैंची धाम में उनके आश्रम आए थे। नीब करौरी बाबा का असली नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था।

उनका जन्म करीब 1900 में उज़र प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के एक गांव में हुआ था और 1973 में उनका निधन हुआ था। कम उम्र में उनका विवाह हो गया था लेकिन बाद में उन्होंने घर-परिवार छोड़कर संन्यासी जीवन अपना लिया। उनके भक्त उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं और उनका मानना है कि बाबा नीब करौरी के पास चमत्कार करने की शक्ति थी। 'हनुमान अंश' की सफलता ने फिल्म जगत को भी हैरान कर दिया है और अब यह चर्चा का विषय है कि आखिर एक ऐसी फिल्म बॉज़्स ऑफिस पर अचानक कैसे छा गई जिसके बारे में पहले कोई चर्चा नहीं थी। फिल्म कारोबार के आंकड़ों पर नजर रखने वाली वेबसाइट 'सैकनिल्क' के अनुसार, पहले सप्ताह की मामूली कमाई के बाद दूसरे सप्ताह में फिल्म का कारोबार और गिर गया था, लेकिन तीसरे सप्ताह से तस्वीर पूरी तरह बदल गई। पीवीआर आईनॉज़्स लिमिटेड के मुज़्य व्यवसाय नियोजन एवं रणनीति अधिकारी कमल ज्ञानचंदानी ने पीटीआई-से कहा, ''किसी ने ऐसी उज़्मीद नहीं की थी।

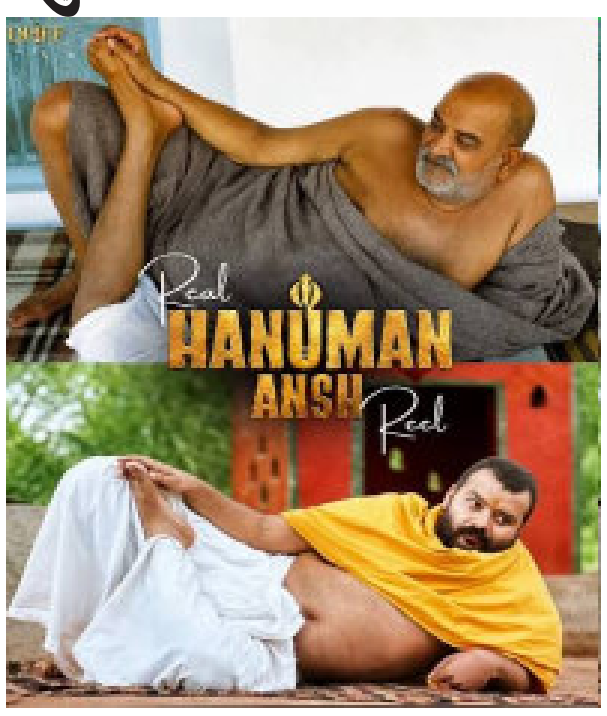

'हनुमान अंश' अपने आप में एक 'केस स्टडी' है। तीसरे सप्ताह में इसे सिनेमाघरों से हटाए जाने की नौबत आ गई थी लेकिन उसी सप्ताह फिल्म ने रज़्तार पकड़ ली और चौथे एवं पांचवें सप्ताह में 'ज़्लॉकबस्टर' बन गई। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है।'' फिल्म उद्योग से जुड़े कई व्यक्तियों और फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि आस्था पर आधारित सिनेमा के प्रति दर्शकों का आकर्षण नया नहीं है।इससे पहले 1975 में रिलीज हुई 'जय संतोषी मां' और 1977 में आई 'शिरडी के साईं बाबा' से लेकर 2024 में भगवान विष्णु के वराह और नरसिंह अवतारों पर बनी

'महावतार नरसिंह' तक ऐसी फिल्मों ने दर्शकों से लगातार जुड़ाव बनाया है। 'महावतार नरसिंह' ने दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी। फिल्म इतिहासकार एवं अभिलेख विशेषज्ञ एस. एम. एम. औसाजा के अनुसार, धार्मिक और पौराणिक फिल्मों की लोकप्रियता नयी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि दादासाहेब फाल्के की फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' (1913) से ही ऐसी फिल्मों ने बॉज़्स ऑफिस पर अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 'राम राज्य' (1943), वी. शांताराम की 'शकुंतला' (1943) और 'जय संतोषी मां' का उदाहरण दिया। 'जय संतोषी मां' उस समय सिनेमाघरों में आई थी जब 'शोले' भी सिनेमाघरों में लगी थी।

इसके बावजूद 'जय संतोषी मां' ने जबरदस्त सफलता हासिल की। अब सभी की निगाहें नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण' पर हैं, जिसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी मुज़्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी।

उन्होंने कहा, ''भारतीय सिनेमा में पौराणिक फिल्मों की एक विधा हमेशा से रही है और ये फिल्में लगातार सफल भी रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ऐसी फिल्मों का पैमाना कहीं बड़ा हो गया है और बड़े कलाकार भी इनसे जुड़ रहे हैं।'' औसाजा के मुताबिक, बाबा नीब करौरी जैसी आध्यात्मिक हस्तियों के प्रति आस्था किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं रहती और यही वजह है कि उनकी कहानियां व्यापक दर्शक वर्ग से जुड़ पाती हैं। ज्ञानचंदानी का मानना है कि कोविड-19 महामारी के बाद सिनेमाघरों में आस्था पर आधारित फिल्मों की लोकप्रियता अधिक साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। उन्होंने कहा, ''लोग बड़ी संज़्या में सिनेमाघरों में आ रहे हैं और आस्था पर आधारित फिल्मों को पसंद कर रहे है। इससे सिनेमाघरों को एक नया दर्शक वर्ग और एक ऐसी फिल्म विधा मिली है, जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं। यह फिल्म उद्योग के लिए अच्छी खबर है।'' सिनेपोलिस इंडिया के प्रबंध निदेशक देवांग संपत ने कहा कि 'हनुमान अंश' की सफलता से साफ है कि दर्शकों में धार्मिक फिल्मों के लिए विशेष जगह है, लेकिन सिर्फ धार्मिक विषय होना ही सफलता की गारंटी नहीं है।

संपत ने 'कांतारा', 'महावतार नरसिंह' और 'लालो' जैसी फिल्मों का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी सफलता के पीछे कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसे आसानी से दोहराया जा सके और इनमें साझा बात अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहरा जुड़ाव है। मिराज एंटरटेनमेंट लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक दीपक अदवानी ने कहा कि वह अभी इसे किसी नये 'ट्रेंड' का नाम देने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन दर्शकों की पसंद में एक स्पष्ट बदलाव जरूर दिखाई दे रहा है। अदवानी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''इन फिल्मों को जोड़ने वाली कड़ी केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं।

असली बात है उनकी प्रामाणिकता, सांस्कृतिक जुड़ाव और ऐसी कहानी जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से थाम सके।'' उन्होंने कहा कि 'हनुमान अंश' की खासियत यह भी है कि इसने युवाओं के साथ-साथ बुजुर्ग दर्शकों को भी सिनेमाघरों तक खींचा है। अदवानी ने कहा, ''सबसे दिलचस्प बात यही है कि इसकी लोकप्रियता किसी एक उम्र के दर्शकों तक सीमित नहीं है।'' सिनेमाघर संचालकों के मुताबिक, 'हनुमान अंश' की उपलज़्धि इसलिए भी उल्लेखनीय है ज़्योंकि 'टॉज़्सिक' और 'आवारापन 2' जैसी बड़े बजट की फिल्मों की मौजूदगी के बावजूद यह सफल हुई। कुछ सिनेमाघरों में 'हनुमान अंश' का प्रदर्शन किसी सामान्य फिल्म की 'स्क्रीनिंग' जैसा नहीं है। मिराज सिनेमाज समेत कुछ सिनेमाघरों में धार्मिक वातावरण बनाने के लिए फिल्म शुरू होने से पहले या उसकी पृष्ठभूमि में हनुमान चालीसा बजाया जा रहा है। संपत ने बताया कि कुछ दर्शक सिनेमाघर में प्रवेश करने से पहले अपनी इच्छा से जूते-चप्पल उतार देते हैं, जबकि कुछ लोग फिल्म खत्म होने के बाद पर्दे पर अंतिम 'क्रेडिट' (फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों की जानकारी देना) चलने तक खामोशी से अपनी सीट पर बैठे रहते हैं।

ब्रिक्स पर सरकार का एकाधिकार नहीं, खुर्शीद ने विपक्ष को शामिल करने की मांग की

नयी दिल्ली ११/०९ (संवाददाता): सलमान खुर्शीद ने आगामी ब्रिज़्स समिट में भारत का प्रतिनिधित्व पूरे देश का होने की वकालत की है, जिसमें केंद्र सरकार के साथ विपक्ष की भी भागीदारी हो। उन्होंने ब्रिज़्स को दुनिया की आधी आबादी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच एक महत्वपूर्ण पुल है, जिसकी अध्यक्षता में भारत की ज़िज़्मेदारी बढ़ जाती है। खुर्शीद ने 12-13 सितंबर को होने वाली दिल्ली समिट में विपक्ष को शामिल कर इसे एक राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व का स्वरूप देने की अपील की। सीनियर कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने गुरुवार को कहा कि 18वें ब्रिज़्स समिट में भारत का प्रतिनिधित्व सिर्फ़ केंद्र सरकार का नहीं, बल्कि पूरे देश का होना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले इस समिट के लिए बातचीत में विपक्ष को भी शामिल किया जाए।ृह्ढ से बात करते हुए खुर्शीद ने ब्रिज़्स के महत्व पर ज़ोर दिया और कहा कि यह समूह दुनिया की आबादी, व्यापार और उभरती हुई आर्थिक ताकत के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि हर कोई ब्रिज़्स के महत्व को समझता और मानता है। जब दुनिया की आधी आबादी ब्रिज़्स से जुड़ी हो, तो आप बस आँखें बंद करके उस आधी आबादी को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। खुर्शीद ने बताया कि ब्रिज़्स उन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है जिनके भविष्य में ग्लोबल इकॉनमी पर छा जाने की उज़्मीद है, साथ ही यह छोटे विकासशील देशों और %ग्लोबल साउथ% के देशों का भी प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि ये वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो आने वाले समय में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं बनेंगी। साथ ही, ये छोटे देशों और %ग्लोबल साउथ% का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। ब्रिज़्स को विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक संभावित पुल बताते हुए खुर्शीद ने कहा कि ब्रिज़्स को एक पुल के तौर पर भी देखा जा सकता है—ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच का पुल, और वह पुल ब्रिज़्स है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह अत्यधिक विकसित, विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि 2026 में ब्रिज़्स की अध्यक्षता मिलने से भारत की ज़िज़्मेदारी बढ़ गई है और नई दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उज़्मीदें भी हैं। खुर्शीद ने कहा कि अगर हम इस भूमिका को पूरी तरह से निभाते हैं—और आज हमसे ऐसी उज़्मीदें हैं; दुनिया चाहती है कि भारत इस भूमिका को निभाए—तो हमारी अध्यक्षता में यह भूमिका भारत के लिए और भी अहम हो जाती है। इसीलिए हर कोई बड़ी उज़्मीदों के साथ भारत की ओर देख रहा है। कांग्रेस नेता ने आग्रह किया कि ब्रिज़्स की अध्यक्षता को मौजूदा सरकार की पहल से आगे बढ़कर एक राष्ट्रीय ज़िज़्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में हैं और हमें उज़्मीद है कि यह प्रतिनिधित्व सिर्फ़ सरकार का नहीं होगा; यह पूरे देश का, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व होगा।

अंबेदकरवादी बनने का दिखावा क्यों? मायावती का विपक्ष पर निशाना, बोलीं-दिल दिमाग साफ करो

लखनऊ ११/०९ (संवाददाता): यूपी विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, नीला रंग चर्चा का विषय बन गया है ज़्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी (क्चस्क्च) के बीच इसे लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। याद दिला दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी की छात्र शाखा के लिए नीली यूनिफॉर्म लॉन्च की थी। इसके अलावा, यूनिफॉर्म लॉन्च होने से तीन दिन पहले, अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गले में नीला स्कार्फ पहनकर पहुंचे थे। इस कदम से यह धारणा बनी कि स्क्क इसके जरिए दलित वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है।

इस बीच, BSP प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बिना उनका नाम लिए, उन्होंने शुक्रवार को कहा कि क्चस्क्च के नीले रंग को अपनाना, गले में नीला स्कार्फ पहनना, नीले कपड़े पहनना या मंच पर नीला कपड़ा लगाने से किसी पार्टी की जातिवादी सोच नहीं बदलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ङ्ग पर मायावती ने लिखा कि अगर आप सच में

गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और दूसरे उपेक्षित वर्गों की परवाह करते हैं, तो स्क्क और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों को सबसे पहले अपने दिल और दिमाग को साफ करना होगा। सिर्फ नीला रंग अपनाने से कोई अंबेडकरवादी नहीं बन जाता। सरकारीयोजनाएं खोजें

मायावती के भतीजे आकाश आनंद को कांग्रेस में शामिल होने के कथित ऑफ़र पर मायावती ने कहा कि कांग्रेस डूबते हुए जहाज़ की तरह है। कोई भी इसमें शामिल होकर अपने राजनीतिक भविष्य को अंधेरे में ज़्यों डालेगा ? आकाश को क्चस्क्च से निकाले जाने के बाद, उज़र प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा था कि आकाश के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं और उन्हें पूरा सज़्मान दिया जाएगा।

गुरुवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यह पूछा गया कि ज़्या आकाश आनंद स्क्क में शामिल हो सकते हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि आप पत्रकार हैं; आप उनसे आने के लिए कहिए, हम उन्हें शामिल कर लेंगे। इसी तरह, क्चछ्वक्च की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि आकाश आनंद को हमारे साथ जुड़ना चाहिए। उन्हें पूरा सज़्मान और बड़ी ज़िज़्मेदारी दी जाएगी। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। अंबेडकर और कांशी राम का सपना अधूरा है, और हम सब मिलकर उसे पूरा कर सकते हैं।

२०२९ में राहुल गांधी विपक्ष का पीएम चेहरा होंगे या नहीं यह तय करना जल्दबाजी-पृथ्वीराज चौहान

मुंबई ११/०९ (संवाददाता): कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने बुधवार को कहा कि यह तय करना अभी जल्दबाजी होगी कि वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में पार्टी सांसद राहुल गांधी को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उज़्मीदवार के रूप में पेश किया जाएगा या नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़ी प्राथमिकता भाजपा विरोधी मतों का विभाजन रोकना होनी चाहिए। 'पीटीआई-भाषा' के पत्रकारों के साथ समाचार एजेंसी के मुंबई स्थित कार्यालय में बातचीत के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुज़्यमंत्री ने कहा कि सज़ारूढ़ भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता कायम करने को कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समेत 'इंडिया' गठबंधन के घटक दल भाजपा का मुकाबला करने के किसी भी प्रयास में महत्वपूर्ण बने रहेंगे। उन्होंने उज़्मीद जताई कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ मतभेदों के चलते विपक्षी गठबंधन से बाहर हुई द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) फिर से इस गुट में लौट आएगी। यह पूछे जाने पर कि ज़्या 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे, चव्हाण ने कहा, ''आज मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद का चेहरा पेश करेगी या नहीं, अथवा किसे पेश करेगी या 'इंडिया' गठबंधन चुनाव के बाद इस बारे में कोई फैसला करेगा।'' हालांकि, कांग्रेस नेता ने भरोसा जताया कि लोगों के बीच राहुल गांधी की व्यापक स्वीकार्यता पार्टी और उसके सहयोगियों के लिए चुनावी लाभ में तज़्दील हो सकती है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु के प्रभावशाली राजनीतिक दल द्रमुक के फिर से 'इंडिया' गठबंधन में लौटने की उज़्मीद जताई। चव्हाण ने कहा, ''उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। मुझे नहीं पता कि 'इंडिया' गठबंधन की ओर से द्रमुक के साथ कौन बातचीत कर रहा है।'' चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने और युवाओं तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के बीच मतभेदों को एकता कमजोर करने का कारण नहीं बनने देना चाहिए और क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, ''हमारा सबसे बेहतर तरीका यह होगा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विपक्षी वोटों का विभाजन न हो। इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं है,

लेकिन यह असंभव भी नहीं है।हमें प्रयास करना चाहिए।'' चव्हाण (80) की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब 2014 से केंद्र की सज़ा में काबिज भाजपा का मुकाबला करने के लिए अगले आम चुनाव से पहले विपक्षी दल संयुक्त रणनीति बनाने के प्रयासों में जुटे हैं। राहुल के नेतृत्व को लेकर पूछे गए सवाल पर चव्हाण ने कहा कि रायबरेली से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी लगातार पार्टी संगठन को मजबूत करने और युवाओं से जुड़ने के प्रयास कर रहे हैं, जो मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोगों की चिंताओं को समझने और उनका समाधान करने के कांग्रेस के प्रयासों के तहत विभिन्न राज्यों की राजधानियों का दौरा कर रहे हैं तथा संगठनात्मक कार्यक्रमों को संबोधित कर रहे हैं।चव्हाण ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के पेपर लीक को लेकर हुए 'जेन-जी' के आंदोलन से यह स्पष्ट है कि युवा अपने भविष्य, खासकर शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हो रहे हैं।

उन्होंने दावा किया, ''यह आंदोलन व्यवस्था के खिलाफ वास्तविक गुस्से की अभिव्यक्ति था।'' अभियांत्रिकी अभियंता से राजनेता बने चव्हाण ने कहा कि युवा प्रदर्शनकारियों ने जिन चिंताओं को उठाया है, वे भाषा, क्षेत्र और सामाजिक सीमाओं से परे हैं। उन्होंने कहा, ''अंततः सवाल यह है कि हमारे भविष्य का ज़्या होगा और हमें किस तरह की आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह ऐसा मुद्दा है जो भाषा, क्षेत्र और राज्यों की सीमाओं से परे है। यह हर चीज से ऊपर है।'' चव्हाण ने कांग्रेस के युवा संपर्क अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि 'छात्रों की गूंज' जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं की चिंताओं को समझना और पार्टी के साथ युवा पीढ़ी का जुड़ाव फिर से मजबूत करना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी को केवल राजनीतिक मुद्दों पर निर्भर रहने के बजाय परीक्षा सुधार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और रोजगार जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा, ''इस समय सबसे अधिक जरूरत अच्छी शिक्षा और मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की है।'' कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्ष 2029 तक कृत्रिम बुद्धिमज़ा (एआई) का रोजगार पर प्रभाव एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। उन्होंने कहा, ''मुझे विशेष रूप से लगता है कि रोजगार पर एआई का प्रभाव इतना व्यापक होगा कि बाकी सभी मुद्दे छोटे पड़ सकते हैं। केवल रोजगार ही मायने रखेगा।'' चव्हाण ने कहा कि कांग्रेस के सामने चुनौती यह होगी कि बढ़ते जन असंतोष को मजबूत जमीनी संगठन के माध्यम से चुनावी लाभ में बदला जाए।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में द्रमुक और उज़र प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसे दल भाजपा का मुकाबला करने की व्यापक विपक्षी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ज़्योंकि इनका अपने-अपने राज्यों में मजबूत प्रभाव है। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि केवल गठबंधन का गणित भाजपा को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा, ''रणनीति एक दिन में तैयार नहीं होगी।

जो कुछ होता है, उससे हम लगातार सीखते रहेंगे।'' चव्हाण ने कहा कि 2029 तक राजनीतिक चर्चा पर आर्थिक मुद्दों का प्रभाव बढ़ेगा, खासकर बेरोजगारी, महंगाई, कृषि और रोजगार के बदलते स्वरूप जैसे विषयों का। चव्हाण ने कहा कि भाजपा का प्रमुख मुद्दा रहे हिंदुत्व की राजनीतिक विचारधारा के रूप में लोकप्रियता कम हो रही है। उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में अपनी अपील खो रहा है। अगर इसे लेकर कोई भ्रम नहीं होता तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को दुनिया को यह समझाने के लिए विदेश यात्रा नहीं करनी पड़ती कि हिंदुत्व का अर्थ ज़्या है।'' आरएसएस प्रमुख भागवत ने हाल में संगठन के शताज़्दी समारोहों के तहत तीन देशों (अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन) की यात्रा पूरी की थी। चव्हाण ने दावा किया कि आरएसएस के संदेश और जमीनी मुद्दों पर भाजपा नेताओं की कथनी-करनी में विरोधाभास है जिनमें भाषा, भोजन, पहनावे और ''बुलडोजर न्याय'' जैसे मुद्दे शामिल हैं।

विविध समाचार

सुबह के नाश्ते में अधिकतर लोग ब्रेड, कार्न फ्लेक्स और कई तले-भुने पदार्थों का सेवन करते हैं लेकिन यही पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का रोगी बना सकते हैं जिसका खुलासा एक नए शोध में हुआ है। व्हाइट ब्रेड, कार्न फ्लेक्स और तले-भुने चावल जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स युक्त भोजन और पेय पदार्थ फेफड़ों के कैंसर के विकास को बढ़ा सकते हैं।

ग्लाइसेमिक सूचकांक और ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) एक संख्या है जो एक विशेष प्रकार के भोजन से संबंधित है। यह व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज के स्तर पर भोजन के प्रभाव को संकेत करता है। गोरी त्वचा, हल्के रंग के बालों और नीली, हरे, रंग की आंखों वाले लोगों में यह एससीसी विकसित होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में 1 हजार 905 रोगियों को शामिल किया था, जिन्हें हाल ही में फेफड़ों के कैंसर की शिकायत हुई थी। इसके साथ ही 2 हजार 413 स्वस्थ व्यक्तियों का भी सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपनी पिछली आहार की आदतों और स्वास्थ्य इतिहास की जानकारी दी।

शोध के दौरान प्रतिदिन जीआई युक्त भोजन करने वालों में जीआई भोजन न करने वालों की तुलना में फेफड़ों के कैंसर का 49 प्रतिशत जोखिम देखा गया। आश्चर्य तौर पर कार्बोहाइड्रेट की सीमा मापने वाले ग्लाइसेमिक लोड (जीएल) का फेफड़ों के कैंसर से कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं मिला। शोधार्थियों का कहना है कि तंबाकू और धूम्रपान का सेवन न करने वालों में भी फेफड़ों के कैंसर के लक्षण मिले हैं जिससे पता चलता है कि आहार के कारक भी फेफड़ों के कैंसर जोखिमों से संबंधित हो सकते हैं।

ज्यादा नारियल पानी से हो सकता है हार्ट अटैक

नारियल पानी पीने के यूं तो कई फायदे हैं। लेकिन गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रोजाना दो गिलास से अधिक नारियल पानी लेना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

पानी की कमी पूरी करने के लिए केवल नारियल पानी पर निर्भर रहना सही नहीं है। इसमें मौजूद पोटैशियम शरीर में जाकर इस तत्व को सामान्य से अधिक कर देता है। जिससे खासकर किडनी व हृदय से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। पोटैशियम शरीर के लिए जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है। सामान्य रूप से व्यक्ति को रोजाना 4700 मिग्रा पोटैशियम की जरूरत होती है। 250 मिली. नारियल पानी में 600 मिग्रा. पोटैशियम होता है। यह शरीर की तंत्रिकाओं, मांसपेशियों और हृदय के सुचारू कार्य करने के लिए जरूरी है।

इन बातों का ध्यान रहे

कई बार हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और डायरिया के पेशेंट्स शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और पानी की कमी को पूरा करने के लिए दिन में कई बार नारियल पानी का सहारा लेते हैं। लेकिन दिनभर में दो गिलास (500 एमएल) से अधिक यह पानी नहीं पीना चाहिए। हार्ट फेल्योर के बढ़ते चांस किडनी शरीर में मौजूद जरूरत से ज्यादा पोटैशियम को बाहर निकालती है। लेकिन इसके मरीजों में इसकी अधिक मात्रा बाहर नहीं निकल पाती और किडनी फेल्योर की आशंका बढ़ जाती है।

इसके अलावा पोटैशियम की अधिकता से हृदय की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं जिससे धड़कनें अनियमित हो जाती हैं जिससे हार्ट फेल्योर के चांस भी बढ़ते हैं। इतना है जरूरी शरीर में पानी की कमी को फल व सलाद से पूरी कर सकते हैं। ये विटामिन और मिनरल तत्व का अच्छा स्रोत होते हैं।

कच्चे पपीते की ड्रिंक दूर भगाए गठिया का दर्द

पैर की उंगलियों, घुटनों और एड़ी में गस के दर्द होता है तो समझिए कि खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है। जब यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में हमारे हाथ और पैरों के जोड़ों में जम जाता है तो उसे गाउट की बीमारी बोलते हैं। हांलाकि इस समस्या से बचने के लिए एक ड्रिंक जो कि कच्चे पपीते और पानी से तैयार की जाती है, जिसको दिनभर पीने से गाउट के दर्द में धीरे - धीरे आराम मिल जाता है।

कैसे रहेगी ताजगी बरकरार

अक्सर हम सब्जियां खरीद कर उन्हें फ्रिज और किचन की टोकरी में रख देते हैं। कुछ चीजों की जगह तो जैसे फिक्स-सी हो गई है। आलू, प्याज जैसी सब्जियों के लिए किचन की टोकरी, तो नींबू, टमाटर और दूसरी सब्जियां फ्रिज की टोकरी में रख दी जाती हैं। यह सोचे बिना कि कौन-सी सब्जी कहां स्टोर करनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर सब्जियों को देखकर उन्हें सही जगह स्टोर किया जाए, तो वह लंबे समय ताजा बनी रहती हैं। आइए जानें ऐसी ही कुछ जरूरी बातें, जो आपकी सब्जियों को बनाए रखेंगी कई दिनों तक फ्रेश।

प्याज

अक्सर लोग प्याज लाने के बाद उसे पॉलीथीन में ही रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी उसकी लाइफ को कम कर देती है। प्याज को अंधेरी, सूखी और ठंडी जगह पर रखा जाए, तो यह लंबे समय तक ठीक रहती है, लेकिन ज्यादा ठंडी जगह पर नहीं रखना चाहिए। इन्हें अखबार में या फिर कागज के बैग में छोटे-छोटे छेद करके लपेट देना चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान रखनी चाहिए, आलू और प्याज को कभी भी एक साथ स्टोर नहीं करना चाहिए क्योंकि आलू में से जो गैस निकलती है वह प्याज को खराब कर सकता है।

नींबू

अक्सर सभी घरों में नींबू काफी तेजी से इस्तेमाल और पसंद किए जाते हैं। अक्सर लोगों को सवाल होता है कि इन्हें लंबे समय तक जूसी और ताजा कैसे रखा जा सकता है? तो आपको बता दें कि नींबू को सिर्फ रेफ्रिजरेटर में ऐसे ही न रखें। इन्हें ज़िप लॉक में रखकर टाइट बंद कर दें। इन्हें काउंटर पर खुला छोड़ने से परहेज करें। ऐसा करने से नींबू का रस सूख जाता है। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि नींबुओं की नमी बरकरार रखने के लिए इन्हें पानी में डालकर छोड़ दें।

केला

केलों को सड़ने से बचाने का सबसे आसान तरीका है, उसके क्राउन (केले का ऊपरी भाग, जहां उसकी जड़ें मिलती हैं) को प्लास्टिक से लपेट कर रख दें। केले में से इथाइलीन नामक गैस निकलती है, जो कि फलों को पकाती है। इसकी जड़ को प्लास्टिक बैग से लपेटकर, उसमें पैदा होने वाली गैस को बचे हुए भाग तक पहुंचने से बचाया जा सकता है। इसकी ज्यादातर गैस जड़ों के माध्यम से ही निकलती है। आप सही केलों को गुच्छे से अलग करके पके हुए केलों को अलग कर सकते हैं क्योंकि पके हुए केले ज्यादा गैस रिलीज करते हैं। इसके अलावा, जड़ों को एक साथ अलग न करें, इससे भी केले जल्दी ब्राउन होते हैं।

टमाटर

टमाटर को स्टोर करने से पहले हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि उन्हें ठंडी जगह पर रखना चाहिए या नहीं। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि फलों और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उन्हें रेफ्रिजरेटर में रख देना, लेकिन यह फॉर्मूला हर बार काम नहीं करता। बिना पके टमाटरों को कमरे के तापमान पर ही रखा जाना चाहिए, ताकि वह ज्यादा जूसी और टेस्टी बन जाएं। ज्यादा तापमान में वह अपना फ्लेवर खो देते हैं। सिर्फ पूरे पके हुए टमाटरों को ही प्लास्टिक बैग में करके फ्रिज में रखा जा सकता है लेकिन ध्यान रखें कि उन्हें इस्तेमाल करने के आधे घंटे पहले ही उन्हें फ्रिज से निकाल कर कमरे के तापमान पर ले आएं।

आलू

लगभग हर घर की किचन में दिखने वाला आलू, काफी बहुमुखी होता है। लेकिन जब हम इन्हें अंकुरित देखते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। इन्हें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती। बस, इन्हें जाली वाले बैग में रख दें। अगर आप इन्हें ठंडी जगह पर स्टोर कर देंगे, तो इनमें उपस्थित स्टार्च शुगर में बदलने लगता है, जिससे आपके खाने का स्वाद खराब हो जाता है। इन्हें रोशनी में बाहर निकाल कर ही रखें और आलुओं को कभी भी धोकर स्टोर न करें क्योंकि नमी से आलू खराब हो जाते हैं।

मसाले

जीरा, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी- ये कुछ ऐसे मसाले हैं, जिन्हें किचन में रखने के बाद देखने की जरूरत पड़ती है। अक्सर, हम इन्हें महत्वपूर्ण नहीं समझते और किचन के कैबिनेट में रखकर भूल जाते हैं। उन मसालों को इस्तेमाल करने से बचें, जिनकी टेस्ट और खुशबू खत्म हो चुकी हो। रोशनी, हवा, गर्मी और नमी मसालों के दुश्मन हैं। आप इन्हें टिन के जार में स्टोर कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें कि डिब्बे टाइट बंद हो और उन्हें गैस से दूर रखें।

पनीर

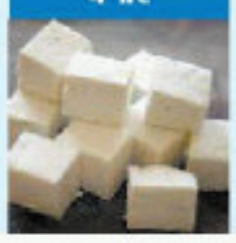

पनीर अक्सर सभी लोगों का फेवरिट होता है इसे प्लास्टिक बैग में लपेट के इसके टेस्ट को खराब नहीं करना चाहिए। इसे स्टोर करते समय ध्यान रखना चाहिए कि यह आसानी से सांस ले सके और सूखे नहीं। इन्हें स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है पार्चमेंट पेपर। वही नहीं, आप इन्हें सुरक्षित रखने के लिए टेप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे न ज्यादा टाइट बंद करना है और न ही ज्यादा ढीला। प्लास्टिक के अलावा, आप इसे एल्यूमीनियम फॉइल पेपर में लपेट सकते हैं। लंबे समय तक ताज़गी बनाए रखने के लिए जब भी आप इसे खोलें, तो कोशिश करें फिर से नए फॉइल में ही लपेटें। इसके साथ ही, अगर आप फ्रिज में पनीर रख रहे हैं, तो ध्यान रहे कि पनीर फ्रिज के नीचे वाले भाग में ही रखें। साथ ही, पनीर को फ्रिजर में रखने से उसकी नरमी खत्म हो जाती है। पनीर के कटे हुए किनारों को टूटने से बचाने के लिए उसके किनारों पर जैतून का तेल और कनोला तेल लगाया जा सकता है।

किचन में शामिल करें ये जड़ी-बूटी

जब भी हम खाना खाने टेबल पर बैठते हैं, तो खाने का स्वाद ही हमारी भूख को संतुष्ट कर पाता है। सिर्फ इसी वजह से कुछ मास्टर्स अपनी डिश बनाने और उसे एक नया स्वाद देने के लिए मसालों से लेकर जड़ी-बूटी और कई चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आयुर्वेदिक कुकिंग में स्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि खाने को सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बने, बल्कि उसमें सभी सामग्री को एक साथ डालकर, किस प्रकार स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाया जाए। हर

सामग्री का अपना एक अलग गुण होता है, जिसके इस्तेमाल से आप शरीर को लाभ पहुंचा सकते हैं।

जड़ी-बूटी, एक तरह से स्वाद को निखारने और मजेदार बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। अगर यह जड़ी-बूटी किचन में देखने को मिले, तो शायद ही कोई कुक ऐसा होगा जो, मामूली डिश को जायकेदार बनाने से चूकेगा। यह ऐसी जड़ी-बूटी हैं, जो खाने में जान डाल देने वाली हैं। आप इन्हें कई तरह से अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। जैसे स्प्रिग (टहनी) को काटकर आप एक सामग्री की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या पास्ता में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इससे करी और मिश्रण भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी, जिनके इस्तेमाल से आप अपने खाने को एक नया स्वाद देने के साथ शरीर को स्वास्थ्य संबंधित कई फायदे दे सकते हैं। आइए बताते हैं इन्हें आप किस तरह अपने किचन में प्रयोग में ला सकते हैं।

कढ़ी पत्ता

साउथ इंडियन क्यूज़ीन की शान कढ़ी पत्ता सबसे ज्यादा तीखे मीट, फ्राइड खाना समेत सांभर, रसम, उपमा, डोसा के भरावन मिश्रण और चटनी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग तो इसे दाल में तड़का लगाने में भी शामिल करते हैं। इसका तीखा स्वाद, भारतीय मसालों के अलावा काली मिर्च के साथ बहुत बढ़िया होता है। खाना बनाते समय तेल में तड़का लगाने के लिए इसकी महक ही काफी होती है।

तेजपत्ता

इस खुशबूदार पत्ते में कई आरोग्य गुण होते हैं। रसोई में यह दाल, करी, बिरयानी, राजमा और छोले के स्वाद को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह सूखा होता है। डिश में इसका हल्का स्वाद देने के लिए आप एक घंटे के लिए खाने को हल्की आंच पर रखकर छोड़ सकते हैं। यह खाया नहीं जाता, इसलिए डिश के बन जाने के बाद इसे निकालकर फेंक दिया जाता है। मार्केट में इसकी ताज़ा पत्तियां भी उपलब्ध हैं। ऐसा कहा जाता है कि रात में ताजे तेजपत्ता को पानी में भिगोकर रखने और सुबह उसी पानी का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल पर नियंत्रण रखा जा सकता है।

पुदीना

पुदीना या मिंट अक्सर सभी के रसोईघर में मौजूद होता है। यह सिर्फ एक मेडिकल गुण रखने वाला ही नहीं, बल्कि डिश को अच्छा स्वाद देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय घरों में पुदीना चटनी, ज्यादातर सभी तरह के खाने के साथ परोसी जाती है। कई बार मिंट का ताज़ा स्वाद गर्मियों में जूस और ड्रिंक्स में भी शामिल किया जाता है। पुदीना, पाचन क्रिया को सही कर, खांसी, जुखाम, शरीर के दर्द और बदन को ठीक करने में मदद करता है।

होली बासिल (तुलसी)

स्टिर फ्राई खाने को हल्का तीखा स्वाद देने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

साइड इफेक्ट से बचाता है आड़ू

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला आडू पेट और लिवर को भी दुरुस्त रखता है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटिन विटामिन-ए का निर्माण करता है जो रेटिना को स्वस्थ रखने के साथ आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला आडू पेट और लिवर को भी दुरुस्त रखता है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटिन विटामिन-ए का निर्माण करता है जो रेटिना को स्वस्थ रखने के साथ आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो ब्रेस्ट कैंसर की आशंका को कम करने के साथ कीमोथैरेपी के साइड इफेक्ट से भी बचाता है। एनीमिया के रोगियों के लिए यह फायदेमंद है।

न्यूट्रीशन इंडेक्स

175 ग्राम आडू लगभग 68 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें 10 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट और 6 फीसदी फाइबर होता है। साथ ही इसमें 11 फीसदी विटामिन-ए और 19 फीसदी विटामिन-सी होता है। आडू में बहुत कम फैट (1 प्रतिशत) होता है इसलिए डाइटिंग करने वालों के लिए यह अच्छा होता है। इसमें कैल्शियम, पोटैशियम व आयरन तत्व होते हैं।

कितनी मात्रा जरूरी

प्रतिदिन 2-3 आडू खाए जा सकते हैं।

ध्यान रखें

इसे दूसरे फलों के साथ मिलाकर न खाएं। भोजन के तुरंत बाद खाने की बजाए इसे आधे घंटे बाद खाएं।

इनके लिए मनाही

जिन्हें एलर्जी और शरीर में सूजन की समस्या हो वे इसे खाने से पहले डॉक्टरी सलाह लें।

रेसिपी

चोको चिप केक

सामग्री

वनीला एसन्स 1 टेबल स्पून, दूध 2/3 कप, चीनी 1 कप, मैदा 1 + 1/4 कप, अंडे 3, बेकिंग सोडा 1 + 1/4 टेबल स्पून, मक्खन 150 ग्राम, चोको चिप 1 कप।

विधि

चीनी और मक्खन को किसी बड़े बाउल में निकालकर अच्छी तरह से तब तक फेंटे जब तक मक्खन चीनी के साथ अच्छे से मिल नहीं जाता (फेंटने के लिए आप मिक्सर का उपयोग कर सकते है)। अंडों को फोड़कर मिक्सर में 1 मिनट तक फेंटना है। अंडे दुगने लगने लगेंगे। एक छलनी में मैदा और बेकिंग सोडा डाल कर छान लीजिये, ताकि इसमें हवा भर जाए। अंडों को चीनी वाले घोल के साथ अच्छे से फेंट लीजिए। इसके बाद वनीला एसेंस चीनी वाले घोल में डाल दें। उसके बाद दूध डाल दीजिये और अच्छी तरह फेंट लीजिए। इसमें मैदा डाल कर अच्छी तरह से फिर से फेंट लीजिए। केक को बर्तन में डालने से पहले उस बर्तन में चारों तरफ तेल या घी लगा लें, ऊपर से एक छोटी चम्मच मैदा चारों तरफ डाल दीजिये। फिर मैदा के घोल को केक बनाने वाले बर्तन मे डाल दीजिए और ऊपर से चोको चिप डाल दीजिए। ध्यान रहे इसे चम्मच से दबाना नहीं है बर्तन को हिला-हिला कर केक के पेस्ट को एक समान कर लीजिए। माइक्रोवेव में 20 मिनट टाइम सेट कर दीजिए या ओवन में 180 डिग्री पर प्री हीट कर लीजिए और 20 से 25 मिनट पर पकने दीजिए। केक में चाकू डाल कर देख लीजिए केक चाकू से चिपक तो नहीं रहा। केक बनकर तैयार है।

बसंती हलवा

सामग्री

2 कप कसा हुआ कद्दू, 1 कप दूध, 200 ग्राम खोया, 1/2 कप चीनी, 1/2 कप मेवा (बादाम, किशमिश, काजू), 1/2 टी स्पून इलायची पाउडर, 1 चुटकी केसर, 1 टे.स्पून देसी घी।

सजाने के लिए: चांदी का वर्क, 1/2 कप सूखा नारियल (कसा हुआ)।

विधि

कद्दू को छीलकर धो लें और कद्दूकस करके पानी डालकर उबाल लें। ठंडा होने पर हाथों से निचोड़कर सारा पानी निकाल दें। कड़ाही में घी डालकर उसमें कद्दू डालकर धीमी आंच पर भून लें। दूध में खोया और केसर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और कड़ाही में डाल दें। जब दूध हलवे में अच्छी तरह मिल जाए, तब उसमें चीनी, इलायची पाउडर और मेवे डालकर 15 मिनट तक चलायें, गर्मागर्म बसंती हलवा चांदी के वर्क और सूखे नारियल से सजाकर सर्व करें।

कलिंग समाचार

संपादकीय

श्रम संहिताएं शोषण का नया औजार

केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर चार श्रम संहिताएं लागू कर दी हैं। इनमें से मजदूरी संहिता 2019 में संसद ने पारित की थी। अन्य तीनों संहिताएं सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 में संसद में पारित की जा चुकी हैं। लेकिन इसके बाद इन्हें लागू करने पर कोई बात नहीं हुई, तो समझा गया कि इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 2024 में मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल भी खत्म हो गया। फिर चुनाव में जीत कर नरेन्द्र मोदी ने तीसरा कार्यभार संभाला, उसके बाद भी इन श्रम संहिताओं पर कोई बात नहीं हुई। अब यकायक मोदी सरकार ने इन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी कर सबको चौंका दिया। सरकार इस फैसले को कर्मचारियों और मज़दूरों के हित में बता रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज, हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिए हैं। यह आज़ादी के बाद मज़दूरों लिए सबसे बड़े और प्रगतिशील सुधारों में से एक है। यह हमारे कामगारों को बहुत ताक़तवर बनाता है। इससे नियमों का पालन भी काफ़ी आसान हो जाएगा और यह ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने वाला है। अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है प्रधानमंत्री ने इन्हें आजमाए बिना ये तो कह दिया कि ये मजदूरों के सबसे प्रगतिशील सुधारों में से एक हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि पिछले कार्यकाल में इन सुधारों को लागू करने से उन्हें किसने रोका था और अब अचानक इन्हें लागू क्यों किया गया। ध्यान रहे कि जिस समय इन संहिताओं को पारित कराया गया, वह कोरोना महामारी का दौर था। जिसने नोटबंदी के बाद त्रस्त जनता की कमर बुरी तरह तोड़ दी थी। लाखों लोग बेघर और बेरोजगार हो गए थे। तब नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का लुभावना नारा दिया था। अभी श्रम संहिताओं को लागू करते वक्त फिर इसी आत्मनिर्भर भारत की बात ही कही जा रही है। मगर मजदूर संगठन अब भी यह नहीं मान रहे हैं कि इनसे मजदूरों का भला होगा। पांच साल पहले भी उन्होंने इसका विरोध किया था, और वे अब भी यही कह रहे हैं कि यह पूंजीपतियों के हितों को देखते हुए बनाए गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मज़दूरों से जुड़े 29 मौजूदा क़ानूनों को 4 कोड में री-पैकेज किया गया है। इसका किसी क्रांतिकारी सुधार के तौर पर प्रचार किया जा रहा है, जबकि इसके नियम अभी तक नोटिफ़ाई भी नहीं हुए हैं। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, %लेकिन क्या ये कोड भारत के मज़दूरों की न्याय के लिए इन 5 ज़रूरी मांगों को हक़ीक़त बना पाएंगे? एसआईआर पर नया विवाद 1.मनरेगा समेत पूरे देश में हर किसी के लिए 400 रुपये की न्यूनतम मज़दूरी 2. राइट टू हेल्थ क़ानून जो 25 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज देगा 3. शहरी इलाक़ों के लिए ए प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 4. सभी असंगठित श्रेत्र के मज़दूरों के लिए पूरी सोशल सिक्योरिटी, जिसमें लाइफ़ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस शामिल है। 5. प्रमुख सरकारी क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी पर रोक। देखना होगा कि मोदी सरकार इन सवालों के जवाब देती है या इन्हें अनदेखा कर देती है। वैसे सरकार का दावा है कि साल 2019 के वेज कोड से कामगारों को न्यूनतम मज़दूरी की गारंटी मिल सकेगी और हर पांच साल में न्यूनतम मज़दूरी की समीक्षा की जाएगी। लेकिन जिस देश में साल में कई बार महंगाई के झटके लगते हैं, वहां मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए पांच साल क्या ज्यादा लंबा वक्त नहीं है। सरकार का यह भी दावा है कि इससे सभी कामगारों को समय पर वेतन मिलने की गारंटी भी दी जाएगी और महिलाओं और पुरुषों को समान मेहनताना मिल सकेगा। एक छोटे से योगदान के बाद सभी कामगारों को ईएसआईसी के हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी और यह सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिहाज़ से काफ़ी अहम होगा। एसआईआर की समय सीमा में संशोधन अच्छी बात है कि इन संहिताओं में इस तरह के प्रावधान हैं, लेकिन महिलाओं को समान वेतन के साथ ही रात में काम के लिए बुलाने की भी छूट दी गई है। बेशक इसमें महिलाओं की सहमति जरूरी होगी, लेकिन इसके बावजूद महिला शोषण के खतरे बढ़ जाएंगे।

बिहार पर भाजपाई जीत का मतलब

अरविन्द मोहन

नतीजों के गणित से भाजपा भले सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन सीटों का सबसे ज्यादा लाभ जदयू को हुआ और चुनाव पूरी तरह नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया।

लेकिन नतीजे आते ही भाजपा बिहार जीतती लग रही है। सरकार पर उसके दबदबे से लेकर विपक्ष के ध्वस्त होने, जदयू के अंदर उसकी ज्यादा चलने और आगे की राजनीति में पक्ष-विपक्ष में कोई और प्रतिद्वंद्वी न दिखने से भाजपा बम बम है। भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मु यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओं में अक्सर एक वाक्य कहा करते हैं-बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।

यह बात वे हिन्दू-मुसलमान ध्रुवीकरण कराने और जातियों में बंटे हिन्दू समाज की जातिगत गोलबंदियों को तोड़ने के लिए कहा करते हैं। लेकिन बिहार विधान सभा के 2020 और 2025 के चुनाव के अनुभव पर यह बात ज्यादा अच्छी तरह लागू होती है। एनडीए नामक गठबंधन तब भी चुनाव में था और नीतीश कुमार भी साथ थे लेकिन राजद के नेतृत्व वाला विरोधी महागठबंधन बस किसी तरह हार पाया- अगर बेइमानी वाले आरोप भूल भी जाएं तो पूरे बिहार स्तर पर वोटों का अंतर मात्र कुछ हजार का था। तब स्पष्ट लगता था कि भाजपा बिहार जीतना चाहती है और नीतीश को किनारे बैठा देना चाहती है।

उसने नीतीश के खिलाफ मीडिया से लेकर मुंहामुंही अभियान चलाया और शासन में ठीक-ठाक काम करके भी उनकी छवि अवांछित बूढ़े वाली हो गई थी। और इस काम में चिराग पासवान की खुली सेवाएं ली गईं जिन्होंने एनडीए में रहते हुए जदयू के सभी उ मीदवारों के खिलाफ लोजपा के उ मीदवार उतारे थे और बुरी पराजय के बावजूद भाजपा से पुरस्कृत हुए।

संयोग ऐसा हुआ कि रिजल्ट ऐसे आये कि नीतीश के बगैर काम नहीं चलने वाला था और फिर उन्होंने जो जो कहा भाजपा ने माना। इस बार एनडीए एक रहा और सेफ रहा। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल और मंगल पांडेय के खिलाफ प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद पंगु बन गई भाजपा के लिए नीतीश की आड़ रही, चिराग अनुशासित रहे और एनडीए ने भारी जीत हासिल कर ली।

नतीजों के गणित से भाजपा भले सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन सीटों का सबसे ज्यादा लाभ जदयू को हुआ और चुनाव पूरी तरह नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया। लेकिन नतीजे आते ही भाजपा बिहार जीतती लग रही है। सरकार पर उसके दबदबे से लेकर विपक्ष के ध्वस्त होने, जदयू के अंदर उसकी ज्यादा चलने और आगे की राजनीति में पक्ष-विपक्ष में कोई और प्रतिद्वंद्वी न दिखने से भाजपा बम बम है। यह चुनाव उसने बिना नेता, बिना कोई नया सामाजिक आधार जोड़े और सिर्फ संसाधनों तथा प्रबंधन के सहारे जीता। और संसाधनों मे कितना उसका अपना फंड था और कितना केंद्र सरकार का यह भी विवाद का मुद्दा हो सकता है।

और जिस तरह से उसने चुनाव के पहले दर्जन भर योजनाओं में धन बढ़ाकर लोगों को अपनी तरफ मोड़ा वह शैली भी नीतीश कुमार की न थी। जदयू के अंदर भी भाजपा की तरफ रुझान रखने वाले नेताओं का दबदबा बढ़ा है। चुनाव लड़ा तो गया नीतीश कुमार के नाम पर लेकिन ठीक चुनाव से पहले केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही नहीं जदयू नेता ललन सिंह ने भी कह दिया कि नेता विधायक दल में चुना जाएगा। मंत्रालयों के बंटवारे में भाजपा कोटे से ज्यादा लोग मंत्री बने और गृह मंत्रालय पहली बार नीतीश कुमार से छिना।ध्द्यह्मश ऋद्धड्डस्र - बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए बनाया गया दवा बाजार बिहार के नतीजों को लेकर विपक्ष अब देश और प्रदेश में एक नया ही मुद्दा उठाया जा रहा है-धांधली का। वह कहां तक जाएगा, कितना सही गलत है यह इस आलेख का विषय नहीं है। लेकिन जो साफ दिख रहा है वह यही है कि अब बिहार की सरकार ही नहीं राजनीति की पूरी डोर ही भाजपा के हाथ में आ गई है। और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडेय जैसों को मंत्री बनाकर भाजपा नेतृत्व ने साफ संकेत दिया है कि उसके लिए मनमानी करना ही सबसे कुशल प्रबंधन है।

जिस तरह उसने चुनाव जीता है उसमें यह बात शामिल थी कि प्रबंधन और संसाधन से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस बार न जाति का कार्ड चला न संप्रदाय का। और अगर पुराने फार्मूले की अ यस्त राजद या सामाजिक न्याय का नया चैंपियन बनाने में लगी कांग्रेस ने दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद जातिगत ध्रुवीकरण करने की कोशिश की तो इस बार उसे भी भाजपा के कुशल रणनीतिकारों ने जंगल राज से जोड़कर यादव राज आने के डर में बदल दिया। यह डर अगड़ों में तो हुआ ही अति पिछड़ा, पिछड़ा(यादव के अलावा), दलितों और मुसलमानों में भी आ गया।

यह नया बिहार है और इसे बनाने का श्रेय भाजपा को दिया जाए न जाए लेकिन इसकी समझ अकेले उसके रणनीतिकारों को थी। बिहार में विकास की बयार बहती हो ऐसा नहीं है पर वह मण्डल-कमंडल की राजनीति से आगे आ चुका है यह कहने में हर्ज नहीं है। और इसकी समझ ज्यादातर राजनैतिक पंडितों को नहीं थी।

इसी मामले में प्रशांत किशोर थोड़े अलग हैं लेकिन उनकी चुनावी लड़ाई की कमियों के बारे में बहुत कुछ कहना पड़ेगा। उन्होंने भी नई राजनीति की जमीन बनाने में एक भूमिका निभाई है। भाजपा की खूबी यह है कि सत्ता में होते हुए और संघ जैसे जड़ संगठन के साथ रहते हुए भी उसने मजे से अपने अंदर बदलाव किया।

हिन्दुत्व का कार्ड मद्धिम पड़ता गया है और मोदी का मैजिक(जिनमें झूठा स्वर्ग दिखाने का खेल शामिल था) टूटते जाने के साथ उसने शासन और डायरेक्ट डिलीवरी का ऐसा दो आधार अपनाया है कि विपक्ष और उसकी सरकारों को दिक्कत होने लगी है।मु य विपक्षी कांग्रेस समेत सारे विपक्ष को सचमुच बहुत कुछ नहीं सूझ रहा है। और कुछ न हो तो वोट चोरी या ईवीएम का मुद्दा उठाते रहने से उस सवाल का महत्व भी कम हुआ है।

बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर यही किया जा रहा है। संयोग से बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अभी चल रहे गहन मतदाता सर्वेक्षण में दिख रही कमजोरियों और विपक्ष के मजबूत दलों के भी शोर मचाने से यह मुद्दा जिंदा है। पर कांग्रेस और विपक्ष 2024 के लोक सभा चुनाव में मिले बेहतर परिणामों के बाद जिस कदर चुप रहा है और बिखरा है उसमें बिहार चुनाव नरेंद्र मोदी और भाजपा की राजनीति को चमकाएंगे क्योंकि अभी तक कभी हाथ न आया बिहार अब उनके हाथ आ गया है।

फिर जिन राज्यों में कांग्रेस या विपक्ष की सरकारें हैं वहां शासन में साल-सवा साल में कुछ नया न कर पाने से भी 2024 में मद्धिम पड़ी मोदी राजनीति को लाभ हुआ है। बिहार के धक्के के बाद विपक्षी कैसे संभलता है और मोदी जी उसका कैसा उपयोग करते हैं इस पर सबकी नजर है। वे बंगाल की तरफ बढ़ने का इशारा लगातार दे रहे हैं। बंगाल में विपक्षी एकता शून्य है लेकिन तृणमूल ने अकेले भाजपा को बाहर रखा है। देखना है कि अब कैसी लड़ाई होती है।

केंद्र की श्रम संहिताएं करती हैं मज़दूरों की सुरक्षा को कमज़ोर

नीलोत्पल बसु

कोई प्रौद्योगिकी को उत्पादन की प्रक्रिया में एक ज़रूरी चीज़ मानता है, तो आज इसका इस्तेमाल सिर्फ़ पूंजी के साथ हो रहा है। एक तरफ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी, लेकिन कामगारों को बराबर सुरक्षा न मिलने से शोषण ज़रूर बढ़ेगा। लेबर कोड का हर नियम इसी तरफ इशारा करता है। हार विधानसभा चुनावों में एनडीए की बड़ी चुनावी जीत और उसके साथ हुई खुशी के तुरंत बाद भारत सरकार ने चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को अधिसूचित कर दिया है। मज़दूरी, औद्योगिक संबंध, काम से जुड़ी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर बनी ये संहिताएं देश के %29 श्रम कानूनों को आसान बनाने% के नाम पर हावी हो गए हैं।

नौकरी की सुरक्षा के सवाल पर, श्रम विभाग की सभी संभावित भूमिकाएं खत्म कर दी जाएंगी। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले 90प्रतिशत कार्यबल को सभी सुरक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास नियुक्ति का अधिकार (अपॉइंटमेंट अथॉरिटी) नहीं है। केंद्र सरकार का दावा है कि लेबर कोड सभी के लिए न्यूनतम मज़दूरी पक्का करेंगे। लेकिन, कई राज्यों को मौजूदा न्यूनतम मजदूरी कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और स्कीम वर्कर्स समेत लाखों कामगार न्यूनतम मजदूरी से बाहर हो जाएंगे, न्यायपूर्ण (फेयर) या लिविंग वेज(जीव चलाने के लिए जरूरी मजदूरी) की तो बात ही छोड़ दें।

यह भी दावा किया जा रहा है कि लेबर कोड्सगिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा लाएंगे। लेकिन, इसके लिए, कोई फंड देने या कोई समयसीमा नहीं है। लेकिन नियोक्ता-कामगार संबंध का कई ज़िक्र के बिना, आधार आधारित व्यवस्था वर्तमान कार्यबल के लिए स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या करेगा? एक और दावा यह है कि नये लेबर कोड के अनुसार %निश्चित समय के लिए रोजगार% से बराबर फायदे पक्के होंगे। सच तो यह है कि यह सिर्फ स्थायी और कोर जॉब्स में स्थायी रूप से अस्थायी स्थिति लाएगा, और सभी स्थायी नौकरियों को अल्पावधि ठेके वाले कार्य से बदल देगा। इससे सर्विस की निरंतरता, वरीयता और असली फायदों का नुकसान होगा और इसके नतीजे में यूनियन कमजोर होगी।

लेबर कोड सरकार को कंप्लायंस के रक्षक और नियामक की भूमिका से हटाते हैं, शिकायत आधारित निरीक्षण की प्रणाली को ही खत्म कर देते हैं और उसकी जगह स्व-प्रमाणीकरण लाते हैं, जो नौकरी करने वालों की सुरक्षा के लिए बनाए गए सभी मौजूदा प्रावधानों को तोड़ने की आजादी का एक नरम शब्द है। एक दावा यह है कि नये लेबर कोड से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), वृक्षारोपण, खनन और विनिर्माण कामगारों की सुरक्षा बेहतर होने की उ मीद है। यह सच से कोसों दूर है। एमएसएमई के कामगार इस कानून के प्रावधानों दायरे से बाहर हैं और सेस उगाही में पारदर्शिता की कोई प्रणाली नहीं है। खनन और वृक्षारोपण जैसे कार्यों जिनमें दुर्घटना की संभावनाएं अधिक होती हैं, में निरीक्षण कम करने से सिर्फ और ज़्यादा जानलेवा दुर्घटनाएं हो सकती हैं और नियोक्ताओं की ज़ि मेदारी आपराधिकता से मुक्त हो जाएगी।

केंद्र सरकार अपने प्रेस बयान और सोशल मीडिया पर ज़ोर-शोर से कह रही है कि उन्होंने श्रम कानूनों को लेबर कोड से बदलने के लिए कामगारों के साथ हर मुमकिन विचार-विमर्श किया है। आज़ाद भारत में 1966 में बने पहले नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने सरकार, नियोक्ताओं और कामगारों के बीच तीन-तरफ़ा विचार-विमर्श के लिए एक संस्थागत व्यवस्था के तौर पर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस (आईएलसी) आयोजित करने की सिफारिश की थी। ज़्यादा जानें प्रादेशिक समाचार साक्षात्कार संग्रह राजनीतिक विश्लेषण पेपर अखबार संपादकीय लेख संग्रह आर्थिक समाचार बुलेटिन ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट बजट 2019 विश्लेषण राजनीतिक चर्चा मंच हालांकि, पिछले दस सालों में आईएलसी की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी।

इसलिए, जब संसद ने बिना किसी ज़रूरी चर्चा या बहस के लेबर कोड को पारित किया गया, तो यह असल में केंद्र सरकार का एकतरफ़ा हुक्म था, जिसमें मालिकों के अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और कर्मचारियों के सामूहिक अधिकारों और मोलभाव करने की कोशिशों को अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया, और ज़ाहिर है, विरोध करने के अधिकार को भी आपराधिक बनाया गया। वह ठीक वही समय था जब मालिकों की राय कर्मचारियों पर एकतरफ़ा थोपी जा रही थी। यह साफ़ है कि लेबर कोड का असली मकसद ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (व्यापार करने में आसानी) को बार-बार एक नारे की तरह दोहराना है। दुख की बात है कि इससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि इससे ज़्यादा निवेश आएगा और नतीजतन रोज़गार की दर भी बढ़ेगी। यह उस कड़वी सच्चाई से पूरी तरह अलग है जो सालों से भारतीय उद्योगों के वार्षिक सर्वक्षणों की रिपोर्टों में सामने आई है। इनसे पता चलता है कि नेट वैल्यू एडिशन में मज़दूरी का हिस्सा लगातार कम हो रहा है, जो 1981-82 में 30.27प्रतिशत से घटकर 2023-24 में सिर्फ़ 15.97 प्रतिशत रह गया है। इसी दौरान, मालिकों का मुनाफ़ा 23.39 प्रतिशत से बढ़कर 51.01 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रक्रिया का असर कामगारों पर और भी ज़्यादा साफ़ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लेबर ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि दशक की औसत विकास दर 2013-14 में 6.7 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 4.8प्रतिशत हो गई है। ज़्यादा जानें अर्थजगत समाचार बजट विश्लेषण सेवाएं खेल जगत समाचार साक्षात्कार वीडियो बॉलीवुड समाचार संग्रह प्रादेशिक समाचार अलर्ट युवा केंद्रित सामग्री मनोरंजन समाचार अखबार साक्षात्कार संग्रह ज़्यादा जानें विशेष रिपोर्ट सदस्यता ई-पेपर सदस्यता राजनीतिक विश्लेषण प्रादेशिक समाचार अलर्ट कविता संग्रह पुस्तकें अंतरराष्ट्रीय समाचार युवा विशेष सामग्री बॉलीवुड समाचार संग्रह अर्थजगत समाचार अखबार सरकार मानती है कि बेरोज़गार पढ़े-लिखे युवाओं की सं या बहुत ज़्यादा है।

2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि अगले दस सालों में हर साल औसतन 85 लाख नौकरियां पैदा होंगी, जिसमें भारत में युवाओं की बेरोज़गारी दर दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा 17.6 प्रतिशत है। नीति आयोग का अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के आईटी सेक्टर में 20 लाख प्रौद्योगिक नौकरियों पर असर डाल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लेबर ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें लगे लोगों की दशकीय विकास दर, जो 2004-05 और 2013-14 के बीच यह 7.14 प्रतिशत थी, वह 2014-15 और 2023-24 के बीच घटकर 5.92 प्रतिशत रह गयी है। ये आंकड़े साफ तौर पर घरेलू मांग में तेज़ी से कमी की ओर इशारा करते हैं। कॉर्पोरेट्स और नियोक्ताओं पर श्रमिकों का शोषण करने से जुड़ी सभी रोक हटाने से सिर्फ़ असमानता और बेरोज़गारी बढ़ेगी, जो घरेलू मांग को पूरी तरह खत्म करने का नुस्खा है।

ऐसी खराब हालत में निवेश कैसे बढ़ सकता है? लेबर कोड असल में मज़दूरों को और गुलाम बनाने का एक ब्लूप्रिंट हैं। वास्तव में, वे आर्थिक उत्पादन के बुनियादी उसूलों को पूरी तरह कमज़ोर करने का संकेत देते हैं, जिन्हें चलाने के लिए दो चीज़ों- श्रम और पूंजी- की ज़रूरत होती है। अगर सरकार नियोक्ताओं पर से सभी नियम हटाकर और श्रमिकों को सब कुछ झेलने के लिए छोड़ कर, दोनों के बीच का संतुलन खत्म कर देती है, तो पूरी उत्पादन प्रणाली टूट और रुक जाएगी। अगर कोई प्रौद्योगिकी को उत्पादन की प्रक्रिया में एक ज़रूरी चीज़ मानता है, तो आज इसका इस्तेमाल सिर्फ़ पूंजी के साथ हो रहा है।

एक तरफ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी, लेकिन कामगारों को बराबर सुरक्षा न मिलने से शोषण ज़रूर बढ़ेगा। लेबर कोड का हर नियम इसी तरफ इशारा करता है। इसलिए, वे लेबर कोड श्रमिकों के खिलाफ़ एक वर्ग जिहाद बनाते हैं जबकि श्रमबल ज़िंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए, आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है कि मज़दूर मिलकर इसका विरोध करें और इस बुरे सुधार के खिलाफ़ एकजुट होकर संघर्ष करें, जो कॉर्पोरेट मालिकों को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाने और हथियार बनाने का एक बहाना है। अच्छी बात यह है कि मज़दूरों की बढ़ती एकता और किसानों का सबसे बड़ा हिस्सा भी मिलकर इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर सकता है।

बांग्लादेश को खो रहा भारत

चीन बहुत रणनीतिक तरीके से भारत की घेराबन्दी कर रहा है। बांग्लादेश का मामला आश्चर्य के साथ दुखद भी है क्योंकि इसका निर्माण ही भारत की मदद से हुआ था- 1971 में। आज भी वहां से आये लाखों शरणार्थी भारत के नागरिक बनकर सुरक्षित व समृद्ध जीवन जी रहे हैं। भारत सरकार को अपनी कूटनीति पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। मोदी की व्यक्तिगत पसंदगी, आकांक्षाओं तथा छवि चमकाने का जरिया बनाने की बजाय उसे देश हित में ढाला जाना चाहिये ताकि दक्षिण एशिया में भारत का वह स मान तथा प्रतिष्ठा बनी रहे जो उसने 2014 में आई भारतीय जनता पार्टी की बनी केन्द्र सरकार के पहले के 60 वर्षों में अर्जित की थी। शुरुआत यहां से करें कि पहली बार जब नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सभी पड़ोसी मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित कर सभी को चौंका दिया था। उनके इस कदम का स्वागत किया गया था और माना गया था कि वे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे स बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए दक्षेस (सार्क) देशों के सभी राष्ट्रप्रमुख आये थे। इस प्रतिसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने तथा उसका समझदारीपूर्ण लाभ उठाने के बदले भाजपा के आईटी सेल द्वारा यह प्रचारित किया गया कि पहली बार भारत की ताकत को विदेशी स्तर पर स्वीकारा जा रहा है और इसका कारण मोदी हैं। तत्पश्चात भारत लगातार अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति से हटता चला गया जिसमें व्यक्ति से बड़ा देश को मानने, सामूहिकता तथा छोटे-बड़े सभी देशों की स प्रभुता के स मान का भाव था।

विविध समाचार

चितकारा यूनिवर्सिटी ने बाहा एसएई इंडिया के साथ भविष्य की मोबिलिटी पर किया रणनीतिक मंथन

चंडीगढ। चितकारा यूनिवर्सिटी ने बाहा एस.ए.ई. इंडिया आयोजन समिति और ऑटोमोबाइल उद्योग के वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ एक उच्चस्तरीय रणनीतिक बैठक की सह–मेजबानी करते हुए अनुभवात्मक(एक्सपीरिएंशियल) शिक्षा और उद्योग–समेकित इंजीनियरिंग शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में बाहा एस.ए.ई. इंडिया आयोजन समिति के चेयरमैन बलराज सुब्रमण्यम, मानद सचिव जतिन गर्ग, वरिष्ठ सलाहकार डॉ. के.सी. वोरा तथा ऑटोमोटिव होमोलोगेशन विशेषज्ञ एवं एआरएआई के पूर्व निदेशक बलराज भनोट शामिल हुए। चितकारा यूनिवर्सिटी की ओर से प्रेसिडेंट एवं सह–संस्थापक डॉ. मधु चितकारा, कुलपति डॉ. संधीर शर्मा और रजिस्ट्रार डॉ. राकेश शर्मा उपस्थित रहे। स्वागत संबोधन में बाहा एस.ए.ई. इंडिया आयोजन समिति के चेयरमैन, बलराज सुब्रमण्यम ने कहा कि बाहा एस.ए.ई. इंडिया वर्षों से प्रायोगिक शिक्षा और नवाचार के माध्यम से देश के इंजीनियरिंग विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने का कार्य कर रहा है। कुलपति डॉ. संधीर शर्मा ने कहा कि उभरती तकनीकी चुनौतियों के अनुरूप छात्रों को तैयार करने के लिए उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी समय की आवश्यकता है। बैठक के दौरान बाहा एस.ए.ई. इंडिया की यात्रा और उपलब्धियों पर प्रस्तुति दी गई। इसमें बताया गया कि यह प्रतियोगिता आज देश के सबसे प्रतिष्ठित अनुभवात्मक शिक्षण मंचों में शामिल है। वर्तमान में इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैकेनिकल बाहा, ऑटोनॉमस बाहा और हाइड्रोजन बाहा जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थी भविष्य की मोबिलिटी तकनीकों पर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं। बाहा एस.ए.ई. इंडिया 2027 में भाग लेने वाले छात्र प्रतियोगिता के तहत सिंगल–सीटर ऑल–टेरेन वाहनों की अवधारणा तैयार करने से लेकर उनकी डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग विश्लेषण, निर्माण और परीक्षण तक की पूरी प्रक्रिया बाहा एस.ए.ई. इंडिया के नियमों के अनुरूप पूरी करेंगे। इसके बाद वाहनों का स्थिर और गतिशील परीक्षण किया जाएगा, जिसमें इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, नवाचार, सुरक्षा और प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा। बाहा एस.ए.ई. इंडिया 2027 के लिए देशभर से कुल 186 टीमों ने पंजीकरण कराया है। इनमें 102 ई–बाहा, 26 एच–बाहा और 58 एम–बाहा टीमें शामिल हैं। ये सभी टीमें वर्चुअल राउंड में भाग लेंगी, जहां ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञ बग्गी के प्रारंभिक डिजाइन का मूल्यांकन करने के साथ–साथ प्रतिभागियों को तकनीकी मार्गदर्शन भी देंगे।प्रतियोगिता के दौरान ऑटोमोबाइल विषय पर आधारित एक तकनीकी क्विज भी आयोजित की जाएगी। ई–बाहा, एम–बाहा और बाहा एस.ए.ई. इंडिया 2027 का वर्चुअल राउंड 17 से 19 जुलाई, 2026 तक चितकारा यूनिवर्सिटी, पंजाब कैंपस में आयोजित किया जायेंगे। डिजिटल इंजीनियरिंग टूल्स और सिमुलेशन आधारित मूल्यांकन के जरिए टीमों के वाहन डिजाइन, इंजीनियरिंग विश्लेषण और नवाचार का आकलन किया जायेगा और इसके बाद चयनित टीमें प्रतियोगिता के अगले चरण में पहुंचेगी। चितकारा यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट एवं सह–संस्थापक, डॉ. मधु चितकारा, ने कहा कि चितकारा यूनिवर्सिटी का बाहा एस.ए.ई. इंडिया के साथ जुड़ाव विद्यार्थियों को कक्षा में सीखी गई अवधारणाओं को व्यवहारिक नवाचार में बदलने का अवसर देता है। इससे उनकी तकनीकी दक्षता, नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क और समस्या समाधान कौशल का विकास होता है। बैठक में उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने पर भी विचार–विमर्श किया गया, ताकि इंजीनियरिंग शिक्षा को ऑटोमोबाइल और भविष्य की मोबिलिटी इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सके।

एस.आई.आर.–2026 : सी.ई.ओ. पंजाब द्वारा घर–घर गणना चरण को समय से पहले पूरा करने के लिए ई.आर.ओज. का सम्मान

चंडीगढ। निर्वाचन प्रबंधन में उत्कृष्टता को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने आज निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) 2026 के घर–घर गणना चरण को निर्धारित समय–सीमा से पहले पूरा करने में उनके असाधारण समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि, निर्वाचन प्रक्रिया में शुद्धता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के सामूहिक प्रयासों का स्पष्ट प्रमाण है। श्री गुरविंदर सिंह जौहल के नेतृत्व में धरमकोट विधान सभा क्षेत्र (जिला मोगा), घर–घर गणना अभ्यास को पूरा करने वाला राज्य का पहला क्षेत्र बनकर उभरा। इसके बाद श्री सुनील फोगाट, आई.ए.एस., बलाचौर (जिला एस.बी.एस. नगर)य श्री तरसेम चंद, पी.सी.एस., दिर्घबा (जिला संगरूर)य श्री गगनदीप, पी.सी.एस., निहाल सिंह वाला (जिला मोगा)य श्री अमरीक सिंह सिद्धू, पी.सी.एस., बाघा पुराना (जिला मोगा)य श्री सतविंदर पाल रणीके, पी.सी.एस., मोगा (जिला मोगा)य श्रीमती इसमत विजय सिंह, पी.सी.एस., धूरी (जिला संगरूर) और श्री विपन भंडारी, पी.सी.एस., बंगा (जिला एस.बी.एस. नगर) शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों, ईआरओ, एईआरओज, सुपरवाइजरों और बीएलओज के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए श्रीमती मित्रा ने कहा कि यह मील का पत्थर उनके सामूहिक समर्पण और मिशन–आधारित कार्य को दर्शाता है। इस अवसर पर बोलते हुए सी.ई.ओ. ने अधिकारियों की उनके अथक प्रयासों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस चरण का सफलतापूर्वक पूरा होना मजबूत और पूर्णतः डिजिटाइज्ड मतदाता सूची बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल नागरिकों को सशक्त बनाया जा रहा है, बल्कि मतदान की प्रक्रिया में उनका विश्वास भी बढ़ा है। सी.ई.ओ. ने सभी जिलों से एस.आई.आर.–2026 के आगामी चरणों में इसी प्रकार समर्पण के साथ कार्य करते रहने की अपील की। उन्होंने पंजाब के मतदाताओं से भी अपील की कि जिन्होंने अभी तक संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारियों को अपने गणना फॉर्म जमा नहीं करवाए हैं, वे 3 अगस्त (अंतिम तिथि) से पहले ऐसा करना सुनिश्चित करें ताकि उनके नाम 13 अगस्त, 2026 को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूचियों में शामिल किए जा सकें।

पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच स्थगित, 2 मांगों पर बनी सहमति, कृषि मंत्री से होगी मुलाकात

चंडीगढ। अमेरिका–भारत के बीच ट्रेड डील के विरोध में पंजाब के किसानों द्वारा किया जा रहा दिल्ली कूच अब स्थगित हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दिलबाग सिंह दिराजके ने कहा कि हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ मीटिंग हुई। जिसमें दो मांगों पर सहमति बन गई। इसलिए धरना स्थगित कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान से अगले 8–10 दिन में किसानों बातचीत की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। इस दौरान अमेरिका भारत ट्रेड डील पर भी वार्ता होगी। जानकारी के अनुसार किसान शंभू बॉर्डर से वापस लौटने लगे। कुरुक्षेत्र पुलिस ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी रिहा कर दिया। वहीं, किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि कृषि मंत्री राणा की तरफ से कहा कि गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। बता दें कि किसान सुबह ही दिल्ली जाने के लिए पटियाला–अंबाला के बीच बने शंभू बॉर्डर और संगरूर–जींद के बने खनौरी बॉर्डर पहुंच गए थे। इसका पता चलते ही हरियाणा पुलिस ने दोनों बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर उन्हें सील कर दिया। हरियाणा की तरफ से दोनों बॉर्डरों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है।

अबोहर निगम में भाजपा का कब्जा, पूजा वधवा मेयर बनीं, धर्मवीर मलकट सीनियर डिप्टी मेयर निर्वाचित

अबोहर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत मंगलवार को अबोहर नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और हाईकोर्ट की निगरानी में हुई चुनाव प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बहुमत के दम पर नगर निगम पर अपना कब्जा बरकरार रखा। चुनाव में पूजा वधवा को मेयर, धर्मवीर मलकट को सीनियर डिप्टी मेयर और दीपक छापोला को डिप्टी मेयर चुना गया। मतदान प्रक्रिया जिला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर की मौजूदगी में पूरी कराई गई। चुनाव के दौरान भाजपा के सभी पार्षदों ने मतदान किया। पार्टी के विधायक ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतदान के बाद मतगणना पूरी होने पर भाजपा समर्थित तीनों उम्मीदवारों को विजेता घोषित कर दिया गया। नतीजों की घोषणा होते ही नगर निगम परिसर और शहर के विभिन्न हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, एक–दूसरे को बधाई दी और पार्टी के समर्थन में नारे लगाए। जीत के बाद समर्थकों ने इसे संगठन की एकजुटता और जनसमर्थन का परिणाम बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्था की जीत है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के हस्तक्षेप से चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हुई तथा जनता के जनादेश का सम्मान सुनिश्चित हुआ। चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए नगर निगम परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी, जिससे मतदान और मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अब नई टीम के सामने शहर के विकास कार्यों को गति देने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की चुनौती होगी।

लोकतंत्र के गलियारे और बंद होते कपाट

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था आज एक ऐसे अजीबोगरीब दौर से गुजर रही है, जहां जनता द्वारा चुनी गई सरकारें उसी जनता की आंख और कान समझे जाने वाले चौथे स्तंभ यानी प्रेस से दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझ रही हैं। हाल ही में राज्यों के सचिवालयों और विधानसभाओं से आई खबरें, चाहे वह झारखंड हो, कर्नाटक हो या पश्चिम बंगाल, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए शुभ संकेत नहीं हैं। जब सत्ता के शीर्ष गलियारों और नीति निर्माण के केंद्रों के दरवाजे मान्यता प्राप्त पत्रकारों और कैमरामैनों के लिए बंद किए जाने लगें, या उनके प्रवेश को रोस्टर और पास प्रणाली के संकरे दायरों में समेट दिया जाए, तो यह केवल किसी भौगोलिक परिसर में प्रवेश का निषेध नहीं है। यह सीधे तौर पर सूचना के निर्बाध प्रवाह पर प्रशासनिक और वैचारिक पहरा है। सबसे दिलचस्प और चिंताजनक बात यह है कि इस प्रवृत्ति का कोई एक निश्चित राजनीतिक भूगोल या वैचारिक दल नहीं है। विपक्ष में बैठकर जो दल प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा बताते नहीं थकते, सत्ता के सिंहासन पर बैठते ही वे भी उसी गोपनीयता और सुरक्षा की ढाल के पीछे छिपने लगते हैं। कर्नाटक में विधायकों की गोपनीयता के हनन का तर्क दिया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में दशकों पुराने औपनिवेशिक सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धूल झाड़कर पत्रकारों को डराया जाता है। वहीं झारखंड और राष्ट्रीय स्तर पर संसद भवन में कोविड काल के अस्थायी प्रतिबंधों को स्थाई प्रशासनिक अनुशासन का जामा पहना दिया जाता है। सत्ता का यह सार्वभौमिक चरित्र साबित करता है कि समस्या किसी एक चेहरे या दल की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो खुद को जांच, आलोचना और तीखे सवालों के दायरे से बाहर रखना चाहती है। प्रशासनिक स्तर पर तर्क दिए जाते हैं कि गलियारों में बूम और कैमरों की भीड़ से कामकाज प्रभावित होता है या सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए यह आवश्यक है। सतह पर ये तर्क जितने व्यावहारिक दिखते हैं, इनके भीतर की मंशा उतनी ही अपारदर्शी है। यदि एक पत्रकार को केवल जनसंपर्क विभागों द्वारा जारी की गई नपी–तुली, सुसज्जित और एकतरफा प्रेस विज्ञप्तियों पर ही निर्भर रहना पड़े, तो वह पत्रकारिता नहीं, बल्कि सरकार का आधिकारिक प्रोपेगैंडा बनकर रह जाएगी। वास्तविक जांचपरक पत्रकारिता तो सचिवालयों की उन्हीं अनौपचारिक मुलाकातों और फाइलों के पीछे छिपी विसंगतियों से निकलती है, जिससे समय–समय पर बड़े घोटालों का पर्दाफाश हुआ है।एक जीवंत लोकतंत्र केवल पांच वर्ष में एक बार मतदान करने का नाम नहीं है। यह एक सतत चलने वाली जन अदालत है, जहां सरकार को अपने हर फैसले की पारदर्शिता साबित करनी होती है। जब आप सूचना के स्रोतों पर पहरा बैठा देते हैं, तो आप अंततः नागरिकों के सूचना के अधिकार की मूल भावना पर चोट करते हैं। ब्रिटिश काल के शासक प्रेस से डरते थे क्योंकि वे विदेशी थे और उनका लक्ष्य दमन था, लेकिन आज आजाद भारत के जनसेवक अगर अपनी ही जनता के नुमाइंदों से घबराने लगें, तो सोचना होगा कि व्यवस्था में कहांखोट आ गया है? सत्ताधारियों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र की इमारत को मजबूत रखने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता कोई रियायत नहीं, बल्कि अनिवार्य शर्त है। सचिवालयों के ऊंचे और भारी लोह कपाट भले ही कुछ समय के लिए तीखे सवालों को बाहर रोक दें, लेकिन वे जनता के उस भरोसे को भी भीतर आने से रोक देते हैं जिसके दम पर सरकारें बनती हैं। कलम पर पहरा बिठाकर इतिहास में कभी कोई सत्ता अपनी विसंगतियों को छुपा नहीं पाई है, क्योंकि सच को जितना दबाया जाता है, वह उतनी ही तीव्र लहर बनकर लौटता है। समय आ गया है कि सरकारें इन बंद कपाटों को खोलें और लोकतंत्र को वापस उसकी खुली हवा और पारदर्शिता सौंपें। उल्लेखनीय है कि भारतीय लोकतंत्र की संरचना कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के तीन पारंपरिक स्तंभों पर टिकी है। इन तीनों के सुचारू संचालन और उन पर जनता की निगरानी बनाए रखने का गुरुतर दायित्व चौथे स्तंभ यानी मीडिया (प्रेस) पर रहा है। लोकतंत्र की सतत प्रक्रिया में निर्णय लेने वाली संस्थाओं को जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। सचिवालय और विधानसभा वे भौगोलिक और प्रशासनिक केंद्र हैं, जहां जनता की नियति तय करने वाली नीतियां बनती हैं और कानून पारित किए जाते हैं। जब इन केंद्रों के द्वार जनता की आंख और कान समझे जाने वाले पत्रकारों के लिए बंद किए जाते हैं, तो यह केवल भौगोलिक निषेध नहीं होता, बल्कि यह सूचना के प्रवाह पर लगाया गया एक वैचारिक और प्रशासनिक पहरा होता है। झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और यहां तक कि केंद्रीय स्तर पर संसद दीर्घाओं में पत्रकारों के प्रवेश को सीमित करने के निर्णयों ने इस विमर्श को जन्म दिया है कि क्या भारतीय शासन व्यवस्था में पारदर्शिता के स्थान पर चयनात्मक गोपनीयता हावी हो रही है? भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संविधान निर्माताओं ने इसे मूल अधिकारों के भाग–3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)() (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) में ही अंतर्निहित माना था।सर्वोच्च न्यायालय ने समय–समय पर अपने ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने की वकालत की है।रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950) के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है।सकल पेपर्स बनाम भारत संघ (1962) के मामले में न्यायालय ने माना कि राज्य प्रेस के प्रसार को कम करने या उस पर इस तरह के प्रशासनिक प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं रखता जो उसकी स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाधित करे।एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बनाम भारत संघ (1958) में माना गया कि लोकतांत्रिक संस्थानों के संचालन के लिए समाचारों का निर्बाध प्रवाह आवश्यक है। संविधान का अनुच्छेद 19(2) राज्य को संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। जब राज्य सरकारें सचिवालयों में प्रवेश प्रतिबंधित करती हैं, तो वे अक्सर सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा को आधार बनाती हैं। परंतु, क्या प्रशासनिक भवनों में मान्यता प्राप्त संवाददाताओं का सामान्य आवागमन सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है? यहीं पर न्यायिक समीक्षा और विधिक व्याख्याओं के बीच टकराव पैदा होता है। यह प्रवृत्ति किसी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रही है। यह भारतीय राजनीतिक तंत्र की एक संरचनात्मक समस्या है।नौकरशाही और कार्यपालिका द्वारा इन प्रतिबंधों को वैध ठहराने के लिए मुख्य रूप से तीन तर्क दिए जाते हैं– गोपनीयता की रक्षा, कार्यस्थल पर सुगमता और सुरक्षा और सूचना का संस्थागतकरण। सचिवालयों में कई ऐसी फाइलों और नीतियों पर काम चल रहा होता है जो कैबिनेट की मंजूरी से पहले सार्वजनिक होने पर बाजार में अस्थिरता या प्रशासनिक व्यवधान पैदा कर सकती हैं। अधिकारियों का तर्क होता है कि समय से पहले सूचना का लीक होना नीति निर्माण को प्रभावित करता है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद, कैमरों और बूम माइक के साथ गलियारों में मंत्रियों या अधिकारियों को घेरने की प्रवृत्ति बढ़ी है। नौकरशाही का दावा है कि इससे दैनिक प्रशासनिक कार्यों में बाधा आती है और सुरक्षा के लिए भी चुनौती पैदा होती है।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, शनिवार 12 सितंबर 2026 | पृष्ठ-6

बालासोर में मिले पांच ओरंगुटान, आईजीपी बोले- तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को जड़ से खत्म करेंगे

बालासोर ११/०९ (संवाददाता): ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बालासोर के एक जंगल में मिले पांच बेबी ओरंगुटान की संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय तस्करी की जांच शुरू कर दी है। स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (IGP) हिमांशु लाल बात करते हुए कहा कि जांच का फोकस इस संदिग्ध तस्करी में शामिल पूरे नेटवर्क का पता लगाने और ओरंगुटान के सोर्स का पता लगाने पर होगा। उन्होंने कहा, STF इसकी जांच कर रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है और हम सभी नेटवर्क को खत्म कर देंगे; इसमें शामिल सभी गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी निगरानी ष्ठद्बत्त कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम पूरे नेटवर्क की जांच करेंगे कि वे ओरंगुटान को कहां से लाए थे और उन्हें कहां ले जाया जा रहा था। हम वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं से जांच करेंगे। हम पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। मंगलवार सुबह ओडिशा के बालासोर डिवीज़न के भोगराई ज़्लॉक में बड़ापली गाँव के पास पाँच ओरंगुटान मिले। इसके बाद वन विभाग ने इस बात की जाँच शुरू कर दी कि ये जानवर वहाँ कैसे पहुँचे। बालासोर के ष्ठस्त्रह इन्दलकर प्रतीक प्रकाश के अनुसार, वन अधिकारियों को सुबह करीब 6 बजे VSS के एक सदस्य से जानकारी मिली कि बंदर प्रजाति के पाँच जानवर देखे गए हैं। ष्ठस्त्रह ने कहा, जब हमारे कर्मचारी भोगराई ज़्लॉक में बारपाई गाँव के पास उस जगह पर पहुँचे और जाँच की, तो उन्हें पता चला कि वे जानवर असल में ओरंगुटान थे। अधिकारियों ने पाया कि सभी पाँचों जानवर कम उम्र के थे और ज़्यादा घूम-फिर नहीं रहे थे, हालाँकि वे सतर्क और सक्रिय थे। शुरुआत में उन जानवरों को वहीं खाना दिया गया। जब उस जगह पर भीड़ जमा होने लगी, तो वन अधिकारियों ने ओरंगुटान को बचाया और सही जाँच-पड़ताल के लिए उन्हें उदयपुर सेक्शन ऑफिस भेज दिया। ष्ठस्त्रह ने कहा कि जानवरों की कम उम्र और कम हलचल से पता चलता है कि वे खुद इतनी दूर तक नहीं आ सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि सियार, लोमड़ी, कुज़े और लंगूर जैसे जानवरों की मौजूदगी के कारण उस इलाके में रात भर ज़िंदा रहना मुश्किल होता। प्रकाश ने कहा, स्मगलिंग की संभावना हो सकती है, लेकिन अभी हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते ज़्योंकि हमें इससे जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है।

चोरी और खोए 230 मोबाइल फोन पुलिस ने किया जज़्त

भुवनेश्वर ११/०९ (संवाददाता): ऑपरेशन स्माइल के तहत एक बड़ी सफलता में, अंगुल पुलिस ने 230 खोए और चोरी हुए स्मार्टफोन बरामद करके उनके असली मालिकों को लौटा दिए। यह गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाने के मकसद से शुरू की गई पहल का तीसरा चरण है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हैंडओवर के लिए, अंगुल में पुलिस अधीक्षक (स्क्क) के ऑफिस में खोए और बरामद मोबाइल फोन के लिए एक खास डिस्ट्रीज़्यूशन कैंप लगाया गया था। जिन मालिकों ने पहले अपने फोन गुम या चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान उनके डिवाइस मिल गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बरामद स्मार्टफोन की कुल कीमत लगभग 40 लाख रुपये है।इससे पहले, अंगुल पुलिस ने दो अलग-अलग चरणों में लगभग 45 लाख रुपये के 226 स्मार्टफोन लौटाए थे। इस पहल से, जिला पुलिस ने न सिर्फ नागरिकों को उनकी कीमती संपज़ि वापस दिलाने में मदद की है, बल्कि कानून प्रवर्तन में जनता का भरोसा भी मजबूत किया है। अधिकारियों ने कहा कि खोए हुए डिवाइस का पता लगाने और मोबाइल से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। सेंट्रल रेंज पुलिस ष्ठत्त, सत्यब्रत भोई ने मीडियाकर्मियों से कहा, यह तीसरी बार है जब हम मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंप रहे हैं। अंगुल स्क्क ने पहले एक नंबर जारी किया था, जिसके अब अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, हम आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेज करेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे किसी भी खोए या चोरी हुए मामले की तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। गौरतलब है कि इससे पहले एक और घटना में, खुर्दा पुलिस ने कम से कम 28 मोबाइल फोन बरामद किए थे.

कोरापुट के सुनाबेडा में बाघ दिखने की संभावना से दहशत, ट्रैप कैमरे लगाए गए

कोरापुट ११/०९ (संवाददाता): जिले के सुनाबेड़ा कस्बे में एक अज्ञात जंगली जानवर, जिसके बारे में शुरू में बाघ होने की अफवाह थी, के मानव बस्तियों के पास घूमते हुए कथित तौर पर दिखाई देने वाले वीडियो वायरल होने के बाद दहशत फैल गई है। सेमीलीगुडा वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस जानवर के देखे जाने से निवासियों में चिंता बढ़ गई है, जिसके बाद वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। वीडियो के प्रसार के बाद, सुनाबेड़ा में विभिन्न स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए। वन कर्मचारियों ने देर रात लगभग 11ः40 बजे तक इन कैमरों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और जानवर की किसी भी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए रात्रि गश्त की। हालाँकि, वन विभाग ने अभी तक अपने कैमरों में जानवर की कोई तस्वीर कैद नहीं की है। प्रजाति पर अनिश्चितता रिपोर्टों के अनुसार, वायरल फुटेज के बावजूद, वन विभाग ने कहा है कि यह स्थापित नहीं हो पाया है कि जानवर तेंदुआ है या लकड़बग्घा। अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की है कि रिपोर्टिंग के समय कोई पगमार्क नहीं मिले थे, जिससे प्रजाति की पुष्टि करना मुश्किल हो गया है। वीडियो के आधार पर ही शुरुआती आशंका जताई गई थी कि यह तेंदुआ हो सकता है, लेकिन अधिकारियों के बीच आंतरिक चर्चा में यह भी संभावना जताई गई है कि यह रॉयल बंगाल टाइगर की बजाय लकड़बग्घा हो सकता है। वन अधिकारियों ने बताया कि आगे की कार्रवाई ट्रैप कैमरों की फुटेज के ज़रिए जानवर की पहचान पर निर्भर करेगी। सूत्रों के अनुसार, तब तक प्रभावित इलाकों में निगरानी जारी रहेगी। निवासियों में चिंता बनी हुई है हालाँकि अभी तक इस प्रजाति की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वायरल वीडियो ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है।

ओडिशा में ३७ औद्यौगिक परियोजनाओं को मंजूरी

भुवनेश्वर ११/०९ (संवाददाता): ओडिशा में औद्योगिक विकास को गति देने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की लैंड अलॉटमेंट कमिटी ने राज्य में 37 औद्योगिक परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों को 2 सितंबर को हुई कमिटी की बैठक में स्वीकृति दी गई। बैठक की अध्यक्षता हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और IDCO की चेयरपर्सन उषा पाधी ने की। 37 प्रस्तावों में से 24 बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन आवंटन से जुड़े हैं। वहीं, 13 प्रस्तावों का उद्देश्य स्वस्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। अधिकारियों के अनुसार, इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से राज्य में नए उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उज़्मीद है। ओडिशा सरकार लगातार राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और बेहतर औद्योगिक वातावरण तैयार करने पर जोर दे रही है।

IDCO के माध्यम से उद्योगों के लिए जरूरी भूमि और बुनियादी सुविधाएं उपलज्ध कराने का काम किया जाता है। लैंड अलॉटमेंट कमिटी की मंजूरी के बाद संबंधित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे उद्योगों की स्थापना में आने वाली शुरुआती बाधाएं कम होंगी और निवेशकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। मंजूर किए गए बड़े औद्योगिक प्रोजेज़्ट्स से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। इससे न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि सप्लाई चेन नेटवर्क भी मजबूत होगा। IDCO क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले 13 प्रस्तावों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छोटे और मध्यम उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं और बड़ी संज़्या में लोगों को रोजगार उपलज्ध कराते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी राज्य के औद्योगिक विकास के लिए बड़े उद्योगों के साथ-साथ स्वस्थ्य सेज़्टर का मजबूत होना जरूरी है। छोटे उद्योग बड़े उद्योगों की सप्लाई चेन का हिस्सा बनकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं। ओडिशा में खनिज, ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग और अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक संभावनाएं काफी अधिक हैं। सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए लगातार नीतिगत सुधार और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर काम कर रही है। IDCO की ओर से जमीन आवंटन की प्रक्रिया को उद्योगों के लिए आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे निवेशकों को परियोजनाएं शुरू करने में तेजी मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इन परियोजनाओं के लागू होने से राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे स्थानीय कारोबारियों और युवाओं को भी फायदा मिलने की उज़्मीद है। नई परियोजनाओं से रोजगार सृजन के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास को भी मजबूती मिलने की संभावना है। उद्योगों के विस्तार से परिवहन, लॉजिस्टिज़्स और अन्य सहायक क्षेत्रों में भी अवसर पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य ओडिशा को एक मजबूत औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। इसके लिए निवेश, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। IDCO की लैंड अलॉटमेंट कमिटी की यह मंजूरी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

इससे राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी। आने वाले समय में इन परियोजनाओं के माध्यम से ओडिशा के औद्योगिक परिदृश्य में बदलाव आने की उज़्मीद है। बड़े उद्योगों के साथ स्वस्थ्य क्षेत्र के विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल सकती है।

शराब केस में पत्नी बच्चे की हिरासत पर विवाद

सुंदरगढ़ ११/०९ (संवाददाता):ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आबकारी विभाग की एक कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि अवैध शराब कारोबार के मामले में आरोपी पति के घर छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने उसकी पत्नी और दो साल के बच्चे को हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार सुबह करीब 7 बजे सुंदरगढ़ सदर थाना क्षेत्र के बलादमल गांव में हुई। सुंदरगढ़ सदर आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब बिक्री के आरोप में करण नायक के घर पर छापेमारी की थी।

आबकारी अधिकारियों की टीम फुला साहू के नेतृत्व में करण नायक के घर पहुंची थी। विभाग को सूचना मिली थी कि करण नायक अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहा है। इसी आधार पर टीम ने उसके घर की तलाशी ली। हालांकि, छापेमारी के दौरान आबकारी टीम को घर के अंदर से कोई शराब बरामद नहीं हुई। अधिकारियों के अनुसार, टीम को देखकर करण नायक मौके से भागने लगा और भागते समय उसने करीब दो लीटर शराब फेंक दी। आरोप है कि करण नायक को पकड़ने में असफल रहने के बाद आबकारी अधिकारियों ने उसकी पत्नी बेबी नायक को हिरासत में ले लिया।

उस समय महिला अपने दो साल के बेटे के साथ घर पर मौजूद थी। घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने आबकारी विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि यदि मामला महिला के पति से जुड़ा था तो महिला और छोटे बच्चे को हिरासत में लेना उचित नहीं था। वहीं, आबकारी विभाग की ओर से कहा गया कि कार्रवाई अवैध शराब कारोबार के खिलाफ की जा रही थी। अधिकारियों ने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह मौके से भाग गया। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि महिला को उसके छोटे बच्चे के साथ हिरासत में लेने से परिवार को परेशानी हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच की मांग की है।

कानून विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अवैध शराब का कारोबार रोकना प्रशासन की जिज़्मेदारी है, लेकिन कार्रवाई के तरीके को लेकर सवाल उठने के बाद अब यह मामला चर्चा में आ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि आरोपी करण नायक के खिलाफ मामला था तो उसे गिरज़्तार करने के लिए अलग तरीके अपनाए जाने चाहिए थे। पत्नी और बच्चे को साथ ले जाने से परिवार को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। आबकारी विभाग ने अभी तक इस मामले में विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पूरी कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई है।

पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। यदि कार्रवाई में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों पर भी सवाल उठ सकते हैं। सुंदरगढ़ जिले में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग समय-समय पर अभियान चलाता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए छापेमारी की जाती है। इस घटना के बाद अब आबकारी विभाग की कार्रवाई और हिरासत प्रक्रिया को लेकर बहस शुरू हो गई है। स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है और आगे की कार्रवाई अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी।

आरएसपी में 'चेतना जागरूकता से जागृति की ओर' निवारक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

राउरकेला ११/०९ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) के सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष 2026 के तीन माह लंबे सतर्कता जागरूकता अभियान के एक भाग के रूप में 3 सितंबर, 2026 को ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में 'चेतना = जागरूकता से जागृति की ओर' विषय पर निवारक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। समापन समारोह की अध्यक्षता महा प्रबंधक (सतर्कता) एवं ए.सी.वी.ओ., श्री रंजन भारती ने की। विभिन्न विभागों के प्लानिंग अनुभाग से लगभग 100 अधिकारियों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आधारित एक वीडियो प्रदर्शित किया गया तथा निदेशक प्रभारी (डी.आई.सी.), श्री आलोक वर्मा का संदेश भी प्रसारित किया गया। श्री भारती ने इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता अभियान के विषय के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों से अपने कार्यों में उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने का आह्वान किया।

उप महा प्रबंधक (सतर्कता), श्री संदीप बंसल ने सार्वजनिक वसुली विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने वसुली की विभिन्न प्रक्रियाओं पर चर्चा करते हुए प्रत्येक वसुली प्रक्रिया में पी.सी.पी., एस.बी.डी. एवं सी.एम.एम. जी. दिशानिर्देशों का पालन करने के महत्व को रेखांकित किया। उप महा प्रबंधक (सतर्कता), श्री ए.के.बिस्वाल ने 'निवारक सतर्कता' विषय पर सत्र लिया। उन्होंने प्रतिभागियों को सतर्कता विभाग के विभिन्न कार्यों से अवगत कराया तथा बताया कि प्लानिंग अधिकारी अपने कार्यों में पारदर्शिता का किस प्रकार पालन कर सकते हैं। वरिष्ठ प्रबंधक (सतर्कता), श्री एम.के.सिंह ने ए.बी.एम.एस. पर एक सत्र आयोजित किया। उन्होंने ए.बी.एम.एस. नीति के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी तथा प्रतिभागियों को शिकायत दर्ज करने के विभिन्न माध्यमों से अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन श्री संदीप बंसल ने किया।